

My Notes.....

राष्ट्रीय

नई दूरसंचार नीति का मसौदा जारी

केंद्र सरकार ने नई टेलिकॉम पॉलिसी 'नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन्स पॉलिसी 2018' का मसौदा जारी कर दिया है, जिसका लक्ष्य साल 2022 तक 40 लाख नए रोजगार पैदा करने के साथ साथ सेक्टर में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश आकर्षित करना भी है। साथ ही नई दूरसंचार नीति के मसौदे में देश के प्रत्येक नागरिक को 50 mbps ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है।

क्या है मसौदे में

1. इस नई टेलिकॉम पॉलिसी के मसौदे में कर्ज के बोझ से दबे दूरसंचार क्षेत्र को मुश्किल से उबारने के लिए प्रतिबद्धता भी जताई गई है। इसके लिए दूरसंचार कंपनियों की लाइसेंस फीस, स्पेक्ट्रम इस्तेमाल शुल्क, सार्वभौमिक सेवादायित्व कोष के शुल्क की समीक्षा की जाएगी, क्योंकि इन सभी शुल्कों के चलते दूरसंचार सेवा की लागत बढ़ती है।
2. नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन्स पॉलिसी के मसौदे (ड्रॉफ्ट) में कहा गया है कि इसका उद्देश्य डिजिटल कम्युनिकेशन्स सेक्टर में 40 लाख अतिरिक्त नौकरियां पैदा करना और सभी के लिए ब्रॉडबैंड सुविधा उपलब्ध करवाना है। साथ ही इसका उद्देश्य डिजिटल कम्युनिकेशन्स का योगदान कर के जीडीपी के अनुपात में 8 फीसद तक ले जाना है, जो कि साल 2017 में 6 फीसद रहा था।
3. नई नीति के तहत, सरकार का उद्देश्य 50 फीसद घरों में निश्चित लाइन ब्रॉडबैंड पहुंच को सक्षम बनाना और लैंडलाइन पोर्टेबिलिटी सेवाएं शुरू करना है।
4. इसमें हर नागरिक को 50 mbps की ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराने के साथ, 2020 तक देश की सभी ग्राम पंचायतों को 1 gbps और 2022 तक 10 gbps ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का भी लक्ष्य रखा गया है।

इसरो ने बनाई स्वदेशी परमाणु घड़ी

भारतीय अनुसंधान केंद्र (इसरो) ने एक ऐसी परमाणु घड़ी विकसित की है, जिसका इस्तेमाल अब नेविगेशन सैटेलाइट्स में किया जाएगा। इसके जरिए सटीक लोकेशन डेटा मिल सकेगा। अभी तक इसरो को अपने नेविगेशन सैटेलाइट्स के लिए यूरोपियन एरोस्पेस मैनुफैक्चरर ऐस्ट्रियम से परमाणु घड़ी खरीदनी पड़ती है। लेकिन अब इसरो ने दूसरी पार्टी पर निर्भरता को खत्म करने के लिए देसी परमाणु घड़ी विकसित की है, इससे भारत का नेविगेशन सिस्टम (जीपीएस) और ज्यादा मजबूत होगा।

क्या है

1. अहमदाबाद स्थित अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (एसएसी) के निदेशक तपन मिश्रा ने कहा, 'एसएसी ने स्वदेशी परमाणु घड़ी बनाई है और फिलहाल इस घड़ी को परीक्षण के लिए रखा गया है'।
2. एक बार यह सारे परीक्षण पास कर ले, तो 'यह देसी परमाणु घड़ी नेविगेशन सैटेलाइट्स में भी प्रायोगिक तौर पर इस्तेमाल हो सकती है, ताकि पता लग सके कि अंतरिक्ष में यह कब तक टिक सकती है और कितना सटीक डेटा मुहैया करवा सकती है।'

3. सीएसी के निदेशक ने कहा, 'इस देसी परमाणु घड़ी के निर्माण के साथ ही इसरो उन चुनिंदा अंतरिक्ष संगठनों में शामिल हो गया है, जिनके पास यह बेहद जटिल तकनीक है'।
4. हम आयातित परमाणु घड़ी के डिजाइन और प्रौद्योगिकी के बारे में नहीं जानते हैं। लेकिन 'देसी घड़ी हमारे डिजाइन और विनिर्देशों के आधार पर विकसित की गई है। यह घड़ी आयात की जा रही घड़ी से बेहतर है। हमें उम्मीद है कि यह घड़ी पांच साल से ज्यादा काम करेगी।'
5. **भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली (IRNSS) के तहत लॉन्च की गई सभी सातों सैटेलाइट में से तीन में आयात की हुई रुबिडियम परमाणु घड़ी लगी हुई है।** परमाणु घड़ियों के कामकाज पर तपन मिश्रा ने कहा, 'पहले लॉन्च की गई सातों सैटेलाइट में लगी परमाणु घड़ी को एक समय के साथ जोड़ दिया गया था। अलग-अलग ऑर्बिट में लगी सैटेलाइट्स में इन घड़ियों के बीच लगे समय अंतर नेविगेशन रिसीवर पृथ्वी पर किसी वस्तु की सटीक पोजिशनिंग (स्थिति) बताने में मदद करते हैं'।

फ्लैश पवाइंट

1. अगर परमाणु घड़ी में खराबी आती है, तो इसके और अन्य घड़ियों के बीच समय के अंतर ठीक से पता नहीं लगेगा, जिसके परिणामस्वरूप यह किसी भी वस्तु की गलत पोजिशनिंग (स्थिति) बताएगा।
2. परमाणु घड़ियों के अलावा नेविगेशन सैटेलाइट्स में क्रिस्टल घड़ी भी होती हैं, लेकिन ये परमाणु घड़ियों की तरह सटीक जानकारी नहीं देती।
3. यही वजह है कि अगर किसी सैटेलाइट की तीन परमाणु घड़ियां खराब होती हैं, तो नए परमाणु घड़ी के साथ बैकअप सैटेलाइट लॉन्च करनी पड़ती है।
4. इसरो में सूत्र ने बताया कि सात नेविगेशन सैटेलाइट्स में इस्तेमाल हुई 21 परमाणु घड़ियों में से 9 खराब हो गई हैं, इसलिए इसरो 4 बैकअप नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना बना रहा है। सूत्र ने यह भी बताया कि बैकअप सैटेलाइट्स भेजने के लिए इसरो को पहले सरकार से वित्तीय मंजूरी की जरूरत है।
5. बीते महीने, 12 अप्रैल को इसरो ने आईआरएनएसएस-1आइ लॉन्च किया था, जिसने भारत के पहले नेविगेशन सैटेलाइट आईआरएनएसएस-1ए की जगह ली थी।
6. पहले सैटेलाइट की तीनों परमाणु घड़ियों ने काम करना बंद कर दिया था। इस पर तपन मिश्रा ने कहा, 'परमाणु घड़ियां काफी जटिल तकनीक से बनती हैं। ये कई कारणों से बंद हो सकती हैं। सिर्फ भारतीय नेविगेशन सैटेलाइट की ही नहीं, बल्कि गैलिलियो (यूरोपीय संघ का नेविगेशन सिस्टम) की भी परमाणु घड़ियां पहले बंद हो चुकी हैं'।

पोषण अभियान के दायरे में देश के सभी जिले होंगे

केंद्र सरकार वर्ष 2019 तक देश के सभी जिलों को पोषण अभियान में शामिल कर लेगी। केंद्र सरकार ने अभियान को जन आंदोलन बनाने की रूपरेखा तय करते हुए अग्रिम मोर्चे पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं और वालंटियर्स को आधा दर्जन समूहों में बांटकर जिम्मेदारी दी है। पोषण अभियान की निगरानी के लिए बनी राष्ट्रीय समिति की संस्तुति से 11 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंचने का खाका तैयार किया गया है। केंद्र ने आंदोलन की मुहिम में जुटी टीम को प्रोत्साहन राशि देने के लिए डेढ़ सौ करोड़ रुपये का कार्पस फंड बनाया है। अच्छा काम करने वाली टीम को डेढ़ लाख रुपये सालाना दिए जाएंगे। महिला और बाल विकास मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि करीब दो करोड़ कार्यकर्ता पोषण अभियान को जन आंदोलन बनाने की मुहिम में जुटेंगे।

क्या है

1. राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत बने स्वयं सहायता समूहों को दो करोड़ तीन लाख लाभार्थियों तक पहुंचना है। इसमें 23 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूह के सदस्य शामिल होंगे।
2. करीब आठ लाख 69 हजार अध्यापकों को 87 लाख बच्चों तक पहुंचने की जिम्मेदारी दी जाएगी। जबकि 24 लाख से ज्यादा स्वस्थ भारत प्रेरक, आंगनबाड़ी कर्मी, आशा वर्कर, एएनएम और महिला सुपरवाइजर 4.9 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंचेंगी।
3. नेहरू युवा केंद्र एनएसएस, एनसीसी, स्काउट एंड गाइड के करीब एक करोड़ युवाओं को भी इस अभियान से जोड़कर दो करोड़ लाभार्थियों तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया जा रहा है। कोऑपरेटिव और स्वच्छग्रही भी इस अभियान से जोड़े जाएंगे।
4. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक राज्यों को कहा गया है कि वे समुदाय आधारित कार्यक्रमों के आयोजन के लिए जिलों को सीधे फंड आवंटित करें। समुदाय आधारित कार्यक्रमों का आयोजन आंगनबाड़ी कर्मियों, आशा और राष्ट्रीय आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों की ओर से हर माह सुव्यस्थित तरीके से किया जाएगा। कुपोषण के खिलाफ अभियान में लाभार्थियों को संदेश देने के लिए स्थानीय परंपराओं के मुताबिक पूरे देश में कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इसमें गीत संगीत के कार्यक्रम भी होंगे।
5. राज्यों में होने वाले अच्छे कामकाज को दूसरे राज्यों से साझा करने के लिए एक्सचेंज कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अगुवाई में बनी राष्ट्रीय परिषद की बैठक में तय हुआ है कि 640 जिलों तक पोषण अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए हर राज्य में निगरानी व्यवस्था पर खास फोकस होगा। पहले चरण में 315 जिलों को अभियान में शामिल किया गया था। दूसरे चरण में 215 जिले शामिल किए गए थे।

लक्ष्य क्या है

1. शून्य से छह साल तक के बच्चों में बौनेपन को हर साल दो फीसदी कम करना।
2. कम वजन की समस्या में हर साल दो फीसदी की कमी लाना।
3. छह से 59 महीने के बच्चों में एनीमिया हर साल तीन फीसदी तक कम करना
4. 15 साल की किशोर लड़कियों से लेकर 49 वर्ष की महिलाओं में भी एनीमिया का स्तर तीन फीसदी घटाना

अल्पसंख्यकों के लिए नई सौगात

चौथी सालगिरह से पहले सरकार ने अल्पसंख्यक समाज के कल्याण के लिए राह चौड़ी कर दी। कौशल विकास के जरिए उनकी प्रगति को ध्यान में रखते हुए चलाये जा रहे बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम को 196 से बढ़ाकर 308 जिलों में लागू कर दिया गया है। यानी लगभग आधे देश में। इस योजना का नाम भी बदलकर अब प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम कर दिया गया है। 2 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने इस फैसले पर मुहर लगाई। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने इसे 14वें वित्त आयोग की शेष अवधि के दौरान जारी रखने को भी मंजूरी दी है। यह कार्यक्रम अल्पसंख्यक समुदाय में विशेष तौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में संरचना व सुविधाएं मुहैया कराता है।

क्या है

1. मकसद है कि पिछड़ेपन के मामले में राष्ट्रीय औसत और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच खाई कम हो। इसी उद्देश्य से अल्पसंख्यक सघनता वाले शहरों और गावों के क्लस्टर को चिह्नित करने का मानक लचीला बनाया गया।
2. पहले केवल उन शहरों को अल्पसंख्यक सघन माना जाता था जहां उनकी आबादी 50 फीसद हो। अब इसे घटाकर 25 फीसद कर दिया गया है।

3. जाहिर है कि दायरा अब बहुत बड़ा हो गया है। पीएमजीवी के 308 जिलों के अल्पसंख्यक सघनता वाले जिला मुख्यालयों, ब्लॉकों, शहरों में लागू किया जाएगा। जिसमें 109 जिला मुख्यालय, 870 ब्लॉक तथा 321 शहर शामिल होंगे। वित्त समिति ने इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए 3,972 करोड़ रुपये आवंटित करने की सिफारिश की है।
4. मंत्रालय से दी गई जानकारी के अनुसार पीएमजीवीके के अंतर्गत 33 से 40 फीसद संसाधन का निर्धारण विशेष रूप से अल्पसंख्यक महिला केंद्रित परियोजना के लिए आवंटित होगा।

आपदा डेटाबेस पर कार्यशाला संपन्न

आपदा जोखिम न्यूनीकरण डेटाबेस के लिए डेटा संबंधी आवश्यकताओं पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। इससे राष्ट्रीय स्तर का एक आपदा डेटाबेस तैयार करने अथवा सृजन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। स्थानीय स्तर पर प्राप्त एवं सत्यापित डेटा के साथ इस एकीकृत डेटाबेस को विकसित करना हमारे विभिन्न जोखिमों पर करीबी नजर रखने और इस मामले में सुदृढ़ स्थिति सुनिश्चित करने की दिशा में प्रगति करने के लिए अत्यंत आवश्यक है जिसके बिना भारत अपने विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो पाएगा।

क्या है

1. यह डेटाबेस आपदा जोखिमों से निपटने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए 10 सूत्री एजेंडे के क्रियान्वयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिसका उल्लेख नवंबर, 2016 में आयोजित डीडीआर पर एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एएमसीडीडीआर) में किया गया था।
2. इस कार्यशाला का आयोजन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष (यूनिसेफ), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) और आपदा न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय रणनीति (यूएनआईएसडीआर) के सहयोग से किया गया।
3. इस दौरान डेटाबेस में शामिल किए जाने वाले विभिन्न जोखिमों, डेटा संग्रह टेम्प्लेट एवं डेटा एंट्री से जुड़े आईटी प्लेटफॉर्म, सत्यापन, प्रबंधन एवं विश्लेषण पर सामूहिक प्रस्तुतियां दी गईं और इसके साथ ही इन पर सामूहिक चर्चाएं भी हुईं।
4. एनडीएमए के पदाधिकारियों और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों एवं विभागों, राज्य सरकारों, संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न एजेंसियों, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों (एटीआई), आपदा प्रबंधन संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों ने भी इस कार्यशाला में भाग लिया।

युद्धाभ्यास 'विजय प्रहार' का समापन

राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में चल रहे युद्धाभ्यास 'विजय प्रहार' का 9 मई 2018 को समापन हो गया। एक अप्रैल से शुरू हुए इस युद्धाभ्यास में सेना की सप्त शक्ति कमान के 25 हजार सैनिकों ने जमीन व आसमानी युद्ध कौशल की तकनीक पर काम करते हुए परमाणु हमले से मुकाबले का अभ्यास किया। भविष्य में युद्ध होने के हालात में रासायनिक व परमाणु हथियारों से निपटने के लिए सेना के अधिकारियों एवं जवानों ने तपते रेगिस्तान में न्यूक्लियर प्रोटेक्शन सूट पहनकर युद्धाभ्यास किया। 40 दिन तक चले इस अभ्यास के दौरान अधिकारियों व जवानों ने परमाणु हथियार, कठिन पर्यावरण सहित सभी आकस्मिक परिस्थितियों में लड़ने के लिए खुद को तैयार किया है।

क्या है

1. युद्धाभ्यास के अंतिम दिन सप्त शक्ति कमान के कमांडिंग इन चीफ ले. जनरल चेरिश मैथसन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी जवानों के करतब देखने पहुंचे। जनरल मैथसन ने कहा कि इस युद्धाभ्यास के लिए कठिन मापदंड तय किए

- गए थे। इसका प्रारंभ एक आक्रामक रणनीति के तहत वायु व पृथ्वी में समन्वित युद्ध के तौर पर पूरी खुफिया जानकारी इस्तेमाल करते हुए हुआ था।
2. इस दौरान एयर कैवेलरी रणनीति का पूरी तरह से इस्तेमाल किया गया। जवान परमाणु दूषित वातावरण में किसी भी प्रकार की आक्रामक कार्यवाही करने के लिए प्रशिक्षित किए गए।
 3. युद्ध के दौरान जवानों तक रसद पहुंचाने की 'जस्ट इन टाइम' तकनीक का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के इलाकों में जाकर गहराई तक जाकर मार करने का कौशल भी सैनिकों ने दिखाया।

सौ फीसद बायो एथेनॉल वाहन को मिली मंजूरी

सरकार ने सौ फीसद बायो एथेनॉल से बने वाहनों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि उनके मंत्रालय ने वाहन निर्माता कंपनियों बजाज और टीवीएस को इस दिशा में कदम बढ़ाने की अनुमति दे दी है। बायो एथेनॉल धान और गेहूं के भूसे से बनता है। अब ऑटो रिक्शा, बाइक और स्कूटर 100 फीसद बायो एथेनॉल पर चलेंगे।

क्या है

1. गडकरी ने कहा कि कोई इस्तेमाल नहीं होने के कारण धान की पुआल पंजाब और हरियाणा में जला दी जाती है। इससे प्रदूषण भी फैलता है। बायो एथेनॉल से चलने वाले वाहनों के विकास से इस पुआल का इस्तेमाल किया जा सकेगा। एक टन पुआल से 280 लीटर एथेनॉल बनाया जा सकता है।
2. गडकरी ने सरकार के अन्य कदमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा, 'हम हर साल 40,000 हजार करोड़ रुपये के टिंबर, चार हजार करोड़ रुपये की सुगंधित लकड़ियों, 35 हजार करोड़ रुपये के पेपर पल्प और 35 हजार करोड़ रुपये के न्यूजप्रिंट का आयात करते हैं। इस तरह कुल मिलाकर एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का आयात लकड़ियों से संबंधित है।'
3. सरकार ने इसे कम करने पर जोर दिया है। केंद्र ने किसानों को बांस की खेती के लिए प्रोत्साहित किया है, जिससे आयात कम करने में मदद मिली है। पहली बार बांस को पेड़ की श्रेणी में रखा गया है।
4. मीडिया पर राजनीतिक प्रभाव को लेकर भी गडकरी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोग चाहते हैं कि मीडिया स्वतंत्र और पक्षपात रहित हो।

देश के चुनावी इतिहास में पहली बार ई-नामांकन

देश के चुनावी इतिहास में पहली बार पश्चिम बंगाल के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ई-नामांकन पर 8 मई 2018 को कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस मामले में माकपा की बड़ी जीत हुई है। माकपा की ओर से हाई कोर्ट में ई-नामांकन मंजूर करने के लिए दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि 23 अप्रैल को दोपहर बाद तीन बजे तक ई-मेल से माकपा की ओर जितने भी नामांकन दाखिल हुए हैं, उन्हें स्वीकृति दें। साथ ही हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि कितने लोगों ने ई-मेल से नामांकन दाखिल किए हैं, उनकी सूची भी जारी करें। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद 14 मई को होने वाले मतदान को लेकर एक बार फिर संशय के बादल छा गए हैं।

क्या है

1. न्यायमूर्ति विश्वनाथ समाद्वार व न्यायमूर्ति अरिदम मुखर्जी की खंडपीठ ने माकपा द्वारा ईमेल से दाखिल किए गए नामांकन के मामले पर अभूतपूर्व फैसला सुनाया।

2. गौरतलब है कि हाई कोर्ट की एकल पीठ ने पिछले सप्ताह हिंसा की वजह से नौ प्रत्याशियों द्वारा वाट्सएप पर भेजे गए नामांकन की स्वीकृति का निर्देश दिया था। इसके बाद माकपा ने ईमेल से भेजे गए नामांकन को भी स्वीकार करने की मांग करते हुए दो जजों की पीठ में अपील की थी। उसी पर यह फैसला सुनाया गया है।
3. अदालत ने कहा कि आयोग ई-नामांकन स्वीकार करने को लेकर उदासीन था। यदि ई-नामांकन की सुविधा दी जाती तो नामांकन प्रक्रिया के दौरान खून नहीं बहता। नामांकन की संख्या में भी वृद्धि होती।
4. मतदाताओं को अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को चुनने का मौका मिलता, लेकिन आयोग की उदासीनता की वजह से ऐसा संभव नहीं हुआ। बाद में खंडपीठ ने निर्देश दिया कि 23 अप्रैल को दोपहर बाद तीन बजे तक जितने लोगों ने ई-मेल से नामांकन दाखिल किया है, उनके चुनाव लड़ने की व्यवस्था की जाए।
5. कनाडा में उम्मीदवार अपने नामांकन फॉर्म में सभी जरूरी जानकारियां भरकर उसे इंटरनेट के जरिये चुनाव अधिकारियों को भेज सकते हैं। हालांकि, नामांकन की प्रक्रिया खत्म होने के 48 घंटों के भीतर उन्हें चुनाव अधिकारियों से अपने असली दस्तावेजों का सत्यापन कराना जरूरी होता है।

नक्सलियों के लिए समूह गठित

नक्सलियों के आर्थिक स्रोत पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने बहु-अनुशासनिक समूह का गठन किया है। यह समूह नक्सलियों के नेताओं की संपत्ति भी जब्त करेगा। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने 7 मई 2018 को बताया कि समूह में विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारियों को शामिल किया गया है। अधिकारी ने कहा कि समूह का नेतृत्व एक अतिरिक्त सचिव के हाथों में सौंपा गया है और इसमें गुप्तचर ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, राजस्व गुप्तचर निदेशालय, एनआइए और सीबीडीटी (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) और सीबीआइ के प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं।

क्या है

1. समूह में राज्य के खुफिया विभाग और सीआइडी के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) में अलग से शाखा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह कदम वामपंथी आतंकवाद से संबंधित मामलों की जांच के लिए उठाया जा रहा है।
2. अधिकारियों के मुताबिक, देश में चरम वामपंथी आतंकवाद को संदिग्ध गतिविधियों के माध्यम से वित्तीय मदद मिलती है। प्राइवेट ठेकेदारों, खनन ठेकेदारों, ट्रांसपोर्टों और लघु एवं मध्यम उद्योगों के मालिकों से नक्सली लेवी वसूलते हैं। इसके अलावा गैरकानूनी रूप से पत्थर तोड़ने वालों से वसूली की जाती है और नक्सली साहित्य का वितरण किया जाता है।
3. जांच में पता चला कि भाकपा (माओवादी) बिहार-झारखंड विशेष क्षेत्र समिति के सदस्य प्रद्युम्न शर्मा ने पिछले वर्ष एक निजी मेडिकल कॉलेज में अपनी भतीजी के नामांकन के लिए 22 लाख रुपये खर्च किए थे। भाकपा (माओवादी) के एक अन्य सदस्य संदीप यादव ने नोटबंदी के दौरान 15 लाख रुपये दिए थे। यादव की बेटी एक प्रतिष्ठित निजी कॉलेज में पढ़ रही है और उनका बेटा एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र है। एक अन्य नक्सली नेता अरविंद यादव ने अपने भाई को निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में नामांकन कराने पर 12 लाख रुपये खर्च किए थे।
4. प्रवर्तन निदेशालय ने इन चारों के खिलाफ मनी लांड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है और 1.5 करोड़ रुपये व 32 एकड़ जमीन अटैच की है। इसके अलावा नोटबंदी के दौरान एक करोड़ सहित 2.45 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की गई।

संसदीय समिति की रिपोर्ट को नहीं दी जा सकती है चुनौती

सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2018 को साफ किया कि संसदीय समितियों के प्रतिवेदनों की वैधता को अदालतों में न तो चुनौती दी जा सकती है और न ही उन पर सवाल उठाए जा सकते हैं। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि न्यायालय कानून के अनुसार विधायी व्याख्या के मकसद से संसदीय प्रतिवेदनों का जिक्र कर सकते हैं।

क्या है

1. संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में जस्टिस ए के सिकरी , जस्टिस ए. एम. खानविलकर, जस्टिस धनन्जय वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस अशोक भूषण शामिल हैं। संविधान पीठ ने कहा कि न्यायालय संसदीय समिति के प्रतिवेदनों का न्यायिक संज्ञान तो ले सकते हैं परंतु उनकी वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती।
2. पीठ ने कहा कि संविधान में लोकतंत्र के तीनों अंगों के अलग-अलग अधिकारों को रेखांकित किया गया है और न्यायालय को विधायिका तथा न्यायपालिका के बीच संतुलन बनाना है।
3. शीर्ष अदालत ने कहा कि न्यायिक कार्यवाही में संसदीय समिति के प्रतिवेदनों को आधार बनाने से संसदीय विशेषाधिकार का अतिक्रमण नहीं होता है। न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता कल्पना मेहता और महिलाओं और स्वास्थ्य के संबंध में सामा संसाधन समूह की जनहित याचिका पर यह व्यवस्था दी।

तमाम अदालतों में होंगे यौन उत्पीड़न विरोधी पैनल

सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई 2018 को हाइकोर्ट को तमाम अदालतों में यौन उत्पीड़न विरोधी पैनल गठित करने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेशानुसार 2013 कानून के तहत चीफ जस्टिस या हाइकोर्ट के कार्यरत चीफ जस्टिस की ओर से पूरे देश की अदालतों में यौन उत्पीड़न विरोधी समितियां दो महीने के भीतर गठित होंगी।

क्या है

1. आदेश में दिल्ली हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मिश्रा से हाईकोर्ट व जिला अदालतों में पैनल के गठन के लिए कहा गया है।
2. प्रैक्टिस कर रही महिला एडवोकेट द्वारा तीस हजारी जिला अदालत में कुछ वकीलों द्वारा उत्पीड़न की शिकायत वाली याचिका पर चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच सुनवाई कर रही थी।
3. जस्टिस ए. एम. खानविलकर और डी. वाई. चंद्रचूड़ वाली इस बेंच ने महिला वकील और बार नेताओं से अपने विवादों को सुलझाने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने दोनों पक्षों के वकीलों को गिरफ्तार नहीं किए जाने का आदेश दिया।
4. बेंच ने दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को क्रॉस एफआईआर की जांच का निर्देश दिया और इस मामले को पटियाला हाउस कोर्ट ट्रांसफर कर दिया।

हिमित वीर्य केंद्र की स्थापना

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने पूर्णिया के मरंगा में हिमित वीर्य केंद्र का शिलान्यास करते हुए कहा कि हिमित वीर्य केंद्र की स्थापना केंद्र सरकार से 100 प्रतिशत योगदान के साथ राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत 64 करोड़ रुपये की लागत से की जा रही है। इसमें 20 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

क्या है

1. वर्तमान में कृत्रिम निषेचन का कार्य बिहार में सीएमओएफईडी (सुधा) द्वारा किया जा रहा है। कृत्रिम निषेचन के लिए उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले सांडों की आवश्यकता होती है।
2. स्वतंत्रता के बाद से यह पहली सरकार है जो जमीनी स्तर पर किसानों के कल्याण के लिए ठोस कदम उठा रही है। किसानों की स्थिति में सुधार लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2022 तक किसानों की आय

को दोगुनी करने का संकल्प किया है और इसे अर्जित करने के लिए कृषि मंत्रालय पशुपालन, डेयरी एवं मात्स्यिकी विभाग के साथ पूरे मनोयोग से काम कर रहा है।

3. पूर्णिया स्थित हिमित वीर्य केंद्र देश का अत्याधुनिक वीर्य उत्पादन केंद्र होगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन की पहल दिसंबर 2014 में स्वदेशी नस्लों को संरक्षित करने एवं विकसित करने के लिए की गई थी।

नवंबर 2012 के पहले के अपराध पर मान्य नहीं पॉक्सो एक्ट

किशोरी के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल आफेंसेज एक्ट 2012 को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने विशेष टिप्पणी की है। न्यायमूर्ति एसपी गर्ग व न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने स्पष्ट किया कि नवंबर 2012 के पहले हुए यौन अपराध पर पॉक्सो एक्ट मान्य नहीं होगा। यह मामला पॉक्सो एक्ट लागू होने से पहले का है। ऐसे में निचली अदालत द्वारा मामले को पॉक्सो एक्ट के तहत लेने का आधार नहीं है।

क्या है

1. पीठ ने कहा कि पीड़िता की उम्र 16 वर्ष से अधिक है और शारीरिक संबंध उसकी सहमति से बनाए गए थे। ऐसे में दोषियों को दुष्कर्म की धारा के तहत दोषी नहीं माना जा सकता है और निचली अदालत का फैसला खारिज किया जाता है।
2. हालांकि, पीठ ने यह भी कहा कि चूंकि घटना के समय पीड़िता की उम्र 18 साल से कम थी और बालिग दोषियों ने शारीरिक संबंध बनाकर उसका शोषण किया, जिससे उसने बच्चे को जन्म दिया इसलिए वह बच्चे के भरण-पोषण के लिए मुआवजा पाने की हकदार है।
3. पीठ ने तेजिंदर सिंह को पांच लाख रुपये और विक्रम सिंह को आठ लाख रुपये एफडी के रूप में चार सप्ताह में निचली अदालत में जमा कराने का आदेश दिया, जो बच्चे के बालिग होने तक निचली अदालत के आदेश के बगैर नहीं निकाली जा सकेगी।
4. हालांकि, बच्चे की देखरेख के लिए निचली अदालत निर्धारित समय से पहले धनराशि जारी करने के लिए स्वतंत्र है। निचली अदालत ने तेजिंदर सिंह को पॉक्सो एक्ट के अलावा धारा-376 के तहत दस साल की सजा व एक लाख का जुर्माना व धारा-506 के तहत दो साल की सजा सुनाई थी।
5. वहीं, दूसरे दोषी विक्रम सिंह को पॉक्सो एक्ट के अलावा धारा-376 के तहत उम्रकैद व एक लाख का जुर्माना और धारा-506 के तहत दो साल की कैद की सजा सुनाई थी।

यह था मामला

1. हाई कोर्ट में दायर चुनौती याचिका के मुताबिक पीड़िता ने शाहबाद डेयरी थाने में 28 जनवरी 2012 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
2. आरोप था कि बवाना इंडस्ट्रियल एरिया फैंक्ट्री में दोषियों ने चार से पांच महीने पहले उससे कई बार सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता का मेडिकल टेस्ट कराने पर उसके परिजनो को पता चला कि वह आठ माह की गर्भवती है।
3. उसने मार्च 2012 में बच्चे को जन्म भी दिया। बच्चा फिलहाल हरियाणा के निजी अनाथ आश्रम में है। पीड़िता के डीएनए टेस्ट से पता चला कि दोषी विक्रम सिंह बच्चे का पिता है।
4. सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि पीड़िता ने अपने पिता व भाई पर भी कई बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। यह मामला निचली अदालत में विचाराधीन है।

कावेरी प्रबंधन योजना का मसौदा सुप्रीम कोर्ट में पेश

केंद्र सरकार ने कावेरी जल बंटवारे के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अपना मसौदा दाखिल कर दिया है। चार दक्षिणी राज्यों (कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी) के बीच कावेरी जल बंटवारे पर चल रही कानूनी लड़ाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कावेरी प्रबंधन योजना पर मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया था। 14 मई 2018 को मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस ए.एम. खानविलकर और जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की खंडपीठ के समक्ष मसौदा पेश किया गया। पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा, "हम मसौदे को ठीक करने में नहीं जा सकते हैं, लेकिन कोर्ट के आदेशानुसार राज्य और केंद्र में तालमेल ठीक करवा सकते हैं"। अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 मई को होगी। केंद्र की ओर से जो मसौदा पेश किया गया है, उसे संबंधित राज्यों को दिया जाएगा।

किसके हिस्से में कितना पानी?

1. सुप्रीम कोर्ट ने 16 फरवरी को अपने फैसले में कहा था कि अब तमिलनाडु को 177.25 टीएमसी पानी मिलेगा, पहले ये 192 टीएमसी था।
2. जिसका मतलब है कि तमिलनाडु के हिस्से में आने वाला पानी 14.75 टीएमसी घटा दिया गया है।
3. वहीं कर्नाटक को 192 टीएमसी पानी देने का फैसला लिया, यानी ये फैसला कर्नाटक के लिए फायदेमंद रहा।
4. उधर, केरल को 30 टीएमसी और पुडुचेरी को 7 टीएमसी पानी आवंटित किये जाने का फैसला लिया।

क्या है

1. बता दें कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जल संसाधन सचिव उपेंद्र प्रसाद सिंह को हाजिर होने को कहा था, यही कारण रहा कि वह सोमवार को सुनवाई के दौरान मौजूद रहे।
2. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से कहा था कि वे संबंधित राज्यों से बातचीत कर स्कीम को तैयार करें। इस पर केंद्र ने कहा था कि राज्यों की राय के मुताबिक, हम बोर्ड, ऑथरिटी या कमेटी बनाने को तैयार हैं। पिछली बार केंद्र सरकार ने कावेरी जल बंटवारे के फैसले को लागू करने को लेकर योजना तैयार करने के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट से और समय मांगा था।

अन्तरराष्ट्रीय

टूट गई ईरान-अमेरिका के बीच परमाणु डील

ईरान और अमेरिका के बीच वर्ष 2015 में हुई परमाणु डील आखिरकार टूट गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील से हटने का ऐलान तय समय से तीन दिन पहले ही कर दिया। हालांकि उनके ऐलान करने से पहले ही पूरी दुनिया को इसका अंदेशा था। लेकिन इस डील से हटने को लेकर अब अमेरिका कहीं न कहीं अलग-थलग पड़ गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि फ्रांस और जर्मनी ने परमाणु डील से जुड़े रहने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। डील के टूटने के बाद दुनिया के कई बड़े देशों में इसकी आहट सुनाई दी है। फ्रांस और जर्मनी दोनों ने ही इस डील से अमेरिका के पीछे हटने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है।

क्या है

1. ईरान और अमेरिका के बीच हुई इस डील में इन दोनों देशों के अलावा फ्रांस, जर्मनी, रूस और चीन भी शामिल थे।
2. ज्वाइंट कांफ्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन (JCPOA) को ही परमाणु डील के नाम से जाना गया था। वर्ष 2015 में तत्कालीन ओबामा सरकार ने इसको अपनी बड़ी उपलब्धि बताया था।

3. लेकिन वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने इसको ऐतिहासिक भूल और खराब सौदा करार देते हुए इस डील से पीछे हटने का फैसला लिया है। तीन माह तक इस डील को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच पशोपेश का दौर जारी था, जिसका अब पटाक्षेप हो गया है।
4. **बहरहाल इस परमाणु डील के टूटने के बाद भी पांच अहम देश इसके साथ जुड़े हैं।** लेकिन इस डील के टूटने का असर सिर्फ ईरान तक ही सीमित नहीं है। इसका असर कहीं न कहीं भारत पर भी पड़ सकता है।
5. ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत में तेल की आपूर्ति में ईरान काफी बड़ी भूमिका निभाता है। **इसके अलावा ईरान तेल का निर्यात करने में दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है।**
6. वहीं दुनिया में भारत तीसरा सबसे बड़ा तेल का खरीददार है। ऐसे में अमेरिका से डील टूटने का असर भारत और ईरान के बीच तेल के व्यापार पर पड़ सकता है।
7. **वर्ष 2015 में इस डील के होने से पहले अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिए थे,** जिसके बाद मजबूरन भारत को ईरान से तेल की खरीददारी से हाथ खींचने पड़े थे।
8. ऐसे में फिर एक बार भारत को इन्हीं सब से दो-चार होना पड़ सकता है। उनके मुताबिक 2015 में हुई डील के बाद ही भारत को चाबहार प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में मदद मिली थी।
9. **चाबहार ईरान का एकमात्र बंदरगाह है और रूस यूरोप में सामान भेजने का हब है।**
10. **परमाणु डील खत्म करने के पीछे इजरायल को भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है।** इसकी वजह ये है कि कुछ ही दिन पहले इजरायल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने टीवी पर एक प्रजेंटेशन देकर ईरान पर आरोप लगाया था कि उसने डील की आड़ में अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखा है और दुनिया को धोखे में रखा है।

व्लादिमीर पुतिन ने चौथी बार राष्ट्रपति की ली शपथ

व्लादिमीर पुतिन ने 7 मई 2018 को चौथी बार रूस के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। करीब दो दशक लंबा कार्यकाल पूरा कर चुके पुतिन का आज से छह वर्षों का चौथा कार्यकाल शुरू हुआ। रूस के संविधान की शपथ लेकर पुतिन ने कहा, “रूस, उसके वर्तमान और भविष्य के लिए हर संभव कार्य करना मैं अपना कर्तव्य और अपने जीवन का लक्ष्य मानता हूँ।”

क्या है

1. पुतिन 1999 से ही सत्ता में हैं। मार्च में हुए आम चुनाव में उन्हें 76.7 प्रतिशत वोट मिले थे। पुतिन ने रूस के लोगों को उनके समर्थन और प्रेम के लिए धन्यवाद दिया।
2. गौरतलब है कि रूस के राष्ट्रपति के रूप में पुतिन का चौथा कार्यकाल पश्चिम के साथ बेहद तनावपूर्ण संबंध और विपक्ष के विरुद्ध कार्रवाई की पृष्ठभूमि में शुरू हुआ है। महज दो दिन पहले ही विपक्ष के नेता एलेक्सी नावाल्नी सहित करीब 1,600 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। ये लोग देश भर में पुतिन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। यूरोपीय संघ ने पुलिस की कार्रवाई की आलोचना की है।
3. **रूस के राष्ट्रपति ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान 2014 में क्रीमिया को यूक्रेन से अलग कर दिया और सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल - असद के पक्ष से सैन्य अभियान शुरू किया।**
4. पुतिन ने अपने नये कार्यकाल के दौरान रूस में लोगों का जीवन स्तर सुधारने का वादा किया है। हालांकि , पुतिन ने अपने उत्तराधिकारी के संबंध में कोई संकेत नहीं दिये हैं। जबकि यह स्पष्ट है कि अपना चौथा कार्यकाल पूरा होने के बाद संवैधानिक बाध्यताओं के कारण पुतिन 2024 में राष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं लड़ सकते।

मालदीव के विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) की संयुक्त निगरानी

भारतीय नौसेना का अपतटीय निगरानी पोत (एनओपीवी) सुमेधा को 9 से 17 मई, 2018 तक मालदीव के ईईजेड की संयुक्त निगरानी के लिए तैनात किया गया है। यह तैनाती नौसेना के मिशन आधारित तैनाती के हिस्से के रूप में की गई है। यह निगरानी पोत 11 से 12 मई, 2018 तक माले का संचालन भ्रमण करेगा जिसके दौरान यह पोत मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बलों (एमएनडीएफ) के कर्मियों को प्रशिक्षित करेगा।

क्या है

1. समेधा एमएनडीएफ कर्मियों के साथ 12 से 15 मई, 2018 तक मालदीव के ईईजेड की संयुक्त निगरानी करेगा। एमएनडीएफ कर्मी ईईजेड निगरानी पूरी होने पर माले में पोत से उतर जायेंगे।
2. दो अधिकारी और भारतीय नौसेना के मरीन कमांडों (एमएआरसीओ) कैंडर के 8 नाविक मालदीव में दूसरा विषम युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास (एकता 2018) संचालित कर रहे हैं।
3. यह अभ्यास माले से 145 किलोमीटर उत्तर में कंपोजिट ट्रेनिंग सेंटर, माफिलहाफुशी में किया जा रहा है। अभ्यास के दौरान एमएनडीएफ कर्मियों को गोताखोरी उपकरणों के इस्तेमाल और रख-रखाव, चिकित्सा आपात सहित गोताखोरी से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
4. मालदीव में भारत के राजदूत ने भी 6 और 7 मई, 2018 को प्रशिक्षण अभ्यास देखा। भारतीय नौ सेना का सुमेधा पोत 15 मई, 2018 को माले में भारतीय नौसेना के मार्को प्रशिक्षण दल को अलग करेगा।
5. मालदीव ईईजेड की संयुक्त निगरानी द्वीप देश मालदीव के विशाल विशेष आर्थिक क्षेत्र की सुरक्षा करने के लिए भारत सरकार और भारतीय नौसेना का प्रयास है।

9वीं भारत-जापान ऊर्जा वार्ता संपन्न

नई दिल्ली में 9वीं भारत-जापान ऊर्जा वार्ता संपन्न हुई। ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री आर. के. सिंह और जापान के आर्थिक, व्यापार एवं उद्योग मंत्री श्री हिरोशिगे सेको ने बैठक खत्म होने के बाद एक संयुक्त व्यक्तव्य पर हस्ताक्षर किए। दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति जापान और सातवीं आर्थिक शक्ति भारत ने यह महसूस किया कि विश्वसनीय, स्वच्छ और किफायती ऊर्जा तक पहुंच उनके आर्थिक विकास के लिए जरूरी है और इसे हासिल करने के लिए दोनों मंत्री दोनों देशों के ऊर्जा विकास के लिए द्विपक्षीय ऊर्जा सहयोग को और मजबूत करने पर सहमत हुए। दोनों देश विश्वव्यापी ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा तक पहुंच और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर योगदान करने पर भी सहमत हुए।

क्या है

1. संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) के तहत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) को लागू करने के उद्देश्य से भारत और जापान दोनों ने डी-कार्बोनाइजेशन के लिए हाइड्रोजन समेत अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों के विकास और उनकी तैनाती के महत्व को महसूस किया।
2. भारत और जापान दोनों ने परिवर्तनीय नवीकरणीय ऊर्जा की बेहतर पहुंच के लिए ग्रिड स्थिरता की प्रासंगिकता की सराहना की। दोनों देश “अगली पीढ़ी/शून्य उत्सर्जन वाहनों पर नीति वार्ता” के साथ सहयोग करते हुए इलेक्ट्रिक वाहन (ईवीएस) के विकास की दिशा में बातचीत की पहल करने पर सहमत जताई।
3. भारत और जापान दोनों देशों ने ऊर्जा मिश्रण में कोयला आधारित बिजली उत्पादन के निरंतर महत्व पर फिर जोर दिया और कोयले से निकले बिजली संयंत्रों के लिए पर्यावरणीय उपायों पर सहयोग को बढ़ावा देने पर भी सहमति व्यक्त की।

4. भारत और जापान ने ऊर्जा बाजार के बेहतर संचालन के संवर्द्धन के लिए मिलकर एक साथ काम करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की और गंतव्य खंड की छूट के माध्यम से पारदर्शी और विविध तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) बाजार को बढ़ावा देने की पुष्टि की।

आखिर क्या है अमेरिका की स्पेशल 301 रिपोर्ट

पिछले महीने 27 अप्रैल को अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि के कार्यालय ने अपनी स्पेशल 301 रिपोर्ट, 2018 जारी कर अमेरिका में रचनात्मक कृतियों के बढ़ते बाजार के समक्ष उपस्थित मुख्य चुनौतियों को चिन्हित किया है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ने भारत और चीन सहित 12 प्रमुख कॉपीराइट बाजार देशों को स्पेशल 301 कानून के अंतर्गत अपनी प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा है। इस सूची में उन देशों को रखा जाता है जिनके बौद्धिक संपदा अधिकार यानी आइपीआर ढांचे में कमजोर कानून और उनके लचर क्रियान्वयन एवं प्रवर्तन के चलते बौद्धिक संपदा अधिकारों का लगातार उल्लंघन होता है। स्पेशल 301 समीक्षा प्रक्रिया का प्रमुख लक्ष्य अमेरिकी सरकार की उन देशों की पहचान करने में मदद करना है जो न तो बौद्धिक संपदा अधिकारों को प्रभावी और पर्याप्त सुरक्षा देते हैं, अपितु बौद्धिक संपदा

सुरक्षा चाहने वाले अमेरिकी व्यक्तियों को विदेशी बाजार की निष्पक्ष व न्यायसंगत पहुँच बनाने से भी रोकते हैं।

क्या है

1. इस वर्ष की स्पेशल 301 रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य अमेरिका के कॉपीराइट सुरक्षा प्राप्त फिल्म-टेलीविजन कार्यक्रमों, संगीत, वीडियो गेम्स, प्रकाशन, मनोरंजक सॉफ्टवेयर एवं अन्य रचनात्मक सामग्री के लिए विश्व में तेजी से बढ़ रहे डिजिटल बाजार सहित अन्य बाजारों को खोलना है।

फ्लैशबैक

1. रचनात्मकता व नवोन्मेष से उपजी बौद्धिक संपदा का आज किसी भी देश की प्रगति में विशेष महत्व है। रचनात्मक निर्माताओं और उनकी कृतियों को मिली कानूनी सुरक्षा प्रत्येक देश के विकास का एक प्रमुख मापदंड और सूचक है।
2. विभिन्न प्रकार की बौद्धिक संपदा को विभिन्न कानूनी अधिकार प्राप्त हैं जैसे कि साहित्यिक, कलात्मक, संगीत, नाट्य, फिल्म व कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर आदि को कॉपीराइट या प्रतिलिप्या अधिकार, वैज्ञानिक इजाद या खोज का पेटेंट, व्यापारिक नामों, चिन्हों व प्रतीकों पर ट्रेडमार्क और अन्य प्रकार की रचनात्मक सामग्री को अन्य बौद्धिक संपदा संबंधी कानूनी सुरक्षा मिली हुई है।
3. विश्व समुदाय ने भी बौद्धिक संपदा के महत्व को समझते हुए रचनात्मक कृतियों को सर्वप्रथम 1883 में पेरिस संधि, 1886 में बर्न संधि व 1891 में मैडिड संधि के अलावा अनेक अन्य संधियों द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा प्रदान की हुई है।
4. इनमें वर्ष 1995 का टिप्स समझौता व 1996 में कॉपीराइट सुरक्षा का इंटरनेट पर विस्तार करने वाली दो (वाईपो) इंटरनेट संधियां भी बेहद अहम हैं।
5. इन संधियों के फलस्वरूप प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को एक दूसरे के रचनाकारों के बौद्धिक अधिकारों को अपने देश में वही सुरक्षा प्रदान करनी होती है जो वे अपने देश के नागरिकों को देते हैं। बहरहाल इन सभी संधियों और समझौतों के बावजूद सभी देशों में कानूनी व्यवस्था और उनके प्रवर्तन में काफी विरोधाभास के साथ ही तमाम खामियां भी देखने को मिलती हैं।

2. इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अमेरिका चाहता है कि अन्य देश अपने बाजारों में सख्त कॉपीराइट कानून और कुशल क्रियान्वयन तंत्र बनाएं व उसके रचनात्मक उत्पादों की बाजार तक पहुंच बनाने में मौजूद रुकावटों को दूर करें।
3. बौद्धिक संपदा सामग्री हेतु अन्य देशों के बाजारों का खुलना अमेरिका के निर्यात, नौकरियों और वैश्विक स्तर पर अमेरिकी प्रतियोगी क्षमता बढ़ाने में सदैव एक महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हुआ है। स्पेशल 301 इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अमेरिका की एक प्रमुख नीति है।

भारत-दक्षिण अफ्रीका व्यावसायिक शिखर संपन्न

वाणिज्य एवं उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने 29-30 अप्रैल के दौरान दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित भारत-दक्षिण अफ्रीका व्यावसायिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरे का शुभारंभ अनेक द्विपक्षीय बैठकों के साथ हुआ। श्री सुरेश प्रभु ने दक्षिण अफ्रीका के व्यापार एवं उद्योग मंत्री डॉ. रॉब डेविस और स्वित्जरलैंड, बोत्सवाना एवं लेसोथो के मंत्रियों से भेंट की। मंत्री महोदय ने भारत और इन देशों के बीच के ऐतिहासिक संबंधों पर प्रकाश डाला तथा आर्थिक साझेदारी को आगे बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया।

क्या है

1. भारत-दक्षिण अफ्रीका सीईओ फोरम के सदस्यों से भी भेंट की जिन्होंने भारत-अफ्रीका संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों पर पूरा भरोसा व्यक्त किया और इन संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी ओर से भरपूर समर्थन देने का वादा किया।
2. श्री सुरेश प्रभु ने दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय (एसएडीसी) के मंत्रियों से भी मुलाकात की और भारत-एसएडीसी संवाद में भाग लिया जिसमें विभिन्न मंत्रियों एवं कारोबारी हस्तियों ने भाग लिया। इन मंत्रियों एवं कारोबारी हस्तियों ने व्यापार, निवेश एवं आर्थिक सहयोग के जरिए समृद्धि हासिल करने के लिए अपनी ओर से अथक प्रयास करने का संकल्प व्यक्त किया।
3. मंत्री महोदय ने शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित किया और भारत एवं दक्षिण अफ्रीका के बीच समुचित सामंजस्य बैठाने के बारे में चर्चाएं कीं जो विरासत से एकजुट हैं और समृद्धि के लिए एकीकृत हैं। श्री सुरेश प्रभु ने कहा कि यह शिखर सम्मेलन लाभप्रद साबित होगा और भारत एवं दक्षिण अफ्रीका अगले कुछ वर्षों में तेज विकास के पथ पर अग्रसर हो जाएंगे।
4. अपने दौर के आखिर में श्री सुरेश प्रभु ने वहां रह रहे अनिवासी भारतीयों से मुलाकात की और कहा कि वे 150 वर्षों से भी अधिक अवधि से दोनों देशों के बीच एक पुल की भूमिका निभा रहे हैं तथा आर्थिक एवं वाणिज्यिक सहयोग के उज्ज्वल भविष्य की दृष्टि से अनिवासी भारतीयों से काफी उम्मीदें हैं।

यूनेस्को ने अपनी रिपोर्ट में लिखा 'भारत+कश्मीर'

प्रेस की स्वतंत्रता पर अपनी रिपोर्ट के देशों वाले अध्याय में यूनेस्को ने 'भारत + कश्मीर' लिखा है जिसे लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या वैश्विक संस्था कश्मीर का पृथक अस्तित्व मानती है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यूनेस्को- इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट (आईएफजे) की रिपोर्ट 3 मई 2018 को यूनेस्को ऑफिस में जारी की गई।

क्या है

1. रिपोर्ट जारी होने के बाद सवाल-जवाब वाले सत्र में एक सवाल पूछा गया कि इसमें कश्मीर को भारत के साथ विशेष रूप से क्यों लिखा गया है, क्या वह कश्मीर का पृथक अस्तित्व मानते हैं?

2. आईएफजे के दक्षिण एशिया समन्वयक उज्ज्वल आचार्य ने हालांकि कहा , इस मुद्दे का किसी खास राजनीतिक हित से कोई लेना-देना नहीं है और कश्मीर को इस रूप में इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि उसे दक्षिण एशिया के अस्थिर क्षेत्र में रखा गया है।
3. उन्होंने कहा कि पिछले साल की रिपोर्ट में 5-6 संघर्ष जोन थे, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में अस्थिर थे और इस साल कश्मीर पर खास ध्यान है।
4. पिछले साल हमने छत्तीसगढ़, काबु , श्रीलंका पाकिस्तान और नेपाल के कुछ हिस्सों को शामिल किया था।' उन्होंने कहा कि विरोध दर्ज कर लिया गया है और उसे संबंधित लोगों तक पहुंच दिया जाएगा।

हॉग-काँग में मिला द्वितीय विश्वयुद्ध का बम

हॉग-काँग में 11 मई 2018 को पुलिस ने एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मिले द्वितीय विश्वयुद्ध के बम को डिफ्यूज किया। बम को डिफ्यूज करने से पहले वहां मौजूद करीब 1200 लोगों को उस इलाके से बाहर निकाला गया। एक्सपर्ट्स को वान चाइ जिले में करीब 450 किलोग्राम (1000 पाउंड) का बम मिला जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करके दुकान, ऑफिस और रेस्तरां से तकरीबन 1200 लोगों को बाहर निकाला।

क्या है

1. पुलिस का कहना है कि वह बम अमेरिका का बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक, इस साल अब तक तीन इस तरह के बमों का पता लगाया गया है। जिस जगह पर यह बम मिला वहां अभी मेट्रो बनाने का काम चल रहा है।
2. 70 सालों से भी ज्यादा पुराना यह बम 10 मई 2018 को बरामद हुआ था और इसे डिफ्यूज करने में 20 घंटे का समय लगा। जनवरी महीने में इसी साइट पर इस तरह के 2 और बम बरामद किए गए थे।
3. द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान हॉग-काँग में जापान और मित्र राष्ट्रों की सेनाओं के बीच बड़ा भीषण युद्ध हुआ था जिसकी वजह से यहां अक्सर इस तरह के जिंदा बम मिलते रहते हैं। स्थानीय इतिहासकार जेसन वर्डी के मुताबिक 1941 में युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने हॉग-काँग पर भारी हमला किया था।
4. गौरतलब है कि 2016 में भी इसी इलाके में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वाले 6 बिना फटे ग्रेनेड और दो मोटार गोले पाए गए थे। इसके अलावा पुलिस ने 2014 में लगभग एक टन वजन वाले युद्धक बम को डिफ्यूज किया था, जो शहर में पाया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा बम था।

अमेरिका ने खदेड़े रूस के दो बमवर्षक विमान

अमेरिका के दो जेट विमानों ने अलास्का के तट पर रूस के बम वर्षक विमानों की पहचान की। रूस के TU-95 'बीयर' बॉमर्स अलास्का के पश्चिमी तट पर एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में उड़ान भरते नजर आए। यह जानकारी नॉर्थ अमेरिकन एयरोस्पेस डिफेंस कमांड के प्रवक्ता ने दी है।

क्या है

1. अलास्का के NORAD F-22 'लड़ाकू विमानों ने रूस के बमवर्षक विमानों को देखा और उनकी पहचान की। विमानों ने रूस के विमानों का पीछा किया और उस क्षेत्र से बाहर निकाल दिया। वे विमान फिर लौटकर डिफेंस एरिया में नहीं आए।
2. रूस के रक्षा मंत्रालय के हवाले से न्यूज एजेंसी RIA का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय एयरस्पेस में रूस के विमानों का दो F-22 विमानों ने पीछा किया।

3. रूस की सेना के बयान में कहा गया है कि अमेरिका के विमान रूस के विमानों से 100 मीटर दूर ही रहे। बता दें कि ईरान में कथित रासायनिक हमले के बाद अमेरिका और रूस के रिश्तों में और तलखी आ गई है। राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने कहा था कि रूस के साथ संबंध सबसे बुरे दौर में हैं।

चीन ने पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर का शुरू किया समुद्री परीक्षण

चीन ने देश में बने अपने पहले एयरक्राफ्ट करियर का समुद्री परीक्षण शुरू कर दिया है। चीन की ऑफिशियल मीडिया ने विवादित क्षेत्रीय समुद्री इलाके में नेवी की मौजूदगी बढ़ाने और सेना के आधुनिकीकरण करने के चीन के मिशन में इसे एक ऐतिहासिक कदम करार दिया है। चीन की शिन्हुआ न्यूज एजेंसी ने 13 मई 2018 को ही बयान जारी कर कहा, “देश का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर डालियान शिपयार्ड डॉक से अपने पहले समुद्री परीक्षण पर निकल चुका है। इस ट्रायल का मकसद जहाज की विश्वसनीयता और स्थिरता का निरीक्षण करना है।”

क्या है

1. इससे पहले उसने 2012 में पहले एयरक्राफ्ट कैरियर लिआओनिंग को अपनी नौसेना में शामिल किया था। यह सोवियत संघ में बना है जिसको दुरुस्त करके शामिल किया गया था।
2. नौसेना को लिआओनिंग की सेवा मिलने के बाद चीन ने 2013 में ही स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना शुरू कर दिया था।
3. नए कैरियर को अभी तक कोई स्थाई नाम नहीं दिया गया है। हालांकि, इसे कोड नेम 001A के नाम से जाना जाता है। माना जा रहा है कि नया एयरक्राफ्ट कैरियर 2020 से नौसेना में अपनी सेवाएं देना शुरू कर देगा।
4. चीनी नौसेना ने एक बयान में कहा कि एयरक्राफ्ट के ट्रायल का लक्ष्य उसकी विश्वसनीयता और क्षमता को परखना है। यह एयरक्राफ्ट कैरियर 50,000 मीट्रिक टन वजनी है। अभी तक इसे कोई नाम नहीं दिया गया है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को पिछले साल लॉन्च किया गया था लेकिन उसके बाद से ही इसमें हथियारों और दूसरे सिस्टम्स की फिटिंग की जा रही थी।
5. चीन के इस नए एयरक्राफ्ट कैरियर पर 12,000 से ज्यादा उपकरण फिट हैं। रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि इन उपकरणों को चीन की 532 फर्मों ने बनाया है जिनमें से कई निजी फर्म हैं। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में 3,600 से ज्यादा कॅबिन हैं। देशभर के करीब 3,000 वर्कर इस एयरक्राफ्ट पर डेली बेसिस पर काम कर रहे थे।

अर्थशास्त्र

‘हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना’को जारी रखने की स्वीकृति

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कृषि क्षेत्र में छतरी योजना ‘हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना’को 12वीं पंचवर्षीय योजना से आगे यानी 2017-18 से 2019-20 तक जारी रखने को अपनी स्वीकृति दे दी है। इसमें कुल केंद्रीय हिस्सा 33,269.976 करोड़ रुपये का है। छतरी योजना में 11 योजनाएं/मिशन शामिल हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य समग्र और वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाकर तथा उत्पाद पर बेहतर लाभ सुनिश्चित करके किसानों की आय बढ़ाना है। ये योजनाएं 33,269.976 करोड़ रुपये के व्यय के साथ तीन वित्तीय वर्षों यानी 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए जारी रहेंगी।

छतरी योजनाओं के हिस्से के रूप में निम्नलिखित योजनाएं हैं:-

1. बागबानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन (एमआईडीएच) – 7533.04 करोड़ रुपये के कुल केंद्रीय हिस्से के साथ एमआईडीएच का उद्देश्य बागबानी उत्पादन बढ़ाकर, आहार सुरक्षा में सुधार करके तथा कृषि परिवारों को आय समर्थन देकर बागबानी क्षेत्र के समग्र विकास को प्रोत्साहित करना है।
2. तिलहन और तेल पाम पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमओओपी) सहित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) में कुल केंद्रीय हिस्सा 6893.38 करोड़ रुपये का है। इसका उद्देश्य देश के चिन्हित जिलों में उचित तरीके से क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता बढ़ाकर चावल, गेहूँ, दालें, मोटे अनाज तथा वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन बढ़ाना है। यह कार्य व्यक्तिगत कृषि स्तर पर मिट्टी की उर्वरता तथा उत्पादकता बहाल करके और कृषि स्तरीय अर्थव्यवस्था बढ़ाकर किया जाएगा। इसका एक और उद्देश्य खाद्य तेलों की उपलब्धता को सुदृढ़ बनाना और खाद्य तेलों के आयात को घटाना है।
3. सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसए) में 3980.82 करोड़ रुपये का कुल केंद्रीय हिस्सा है। एनएमएसए का उद्देश्य विशेष कृषि परिस्थितिकी में एकीकृत कृषि, उचित मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकी के मेलजोल से सतत कृषि को प्रोत्साहित करना है।
4. 2961.26 करोड़ रुपये के कुल केंद्रीय हिस्से के साथ कृषि विस्तार पर उप मिशन (एसएमई) का उद्देश्य राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों आदि की जारी विस्तार व्यवस्था को मजबूत बनाना, खाद्य और आहार सुरक्षा हासिल करना तथा किसानों का सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण करना है ताकि कार्यक्रम नियोजन और क्रियान्वयन व्यवस्था संस्थागत बनाई जा सके, विभिन्न हितधारकों के बीच कारगर संपर्क कायम किया जा सके, मानव संसाधन विकास को समर्थन दिया जा सके तथा इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रिंट मीडिया, अंतर व्यक्तिगत संचार और आईसीटी उपायों को नवाचारी बनाया जा सके।
5. बीज तथा पौध रोपण सामग्री पर उप मिशन में कुल केंद्रीय हिस्सेदारी 920.6 करोड़ रुपये की है। इसका उद्देश्य प्रमाणित/गुणवत्ता संपन्न बीज का उत्पादन बढ़ाना, एसआरआर में वृद्धि करना, कृषि से बचे बीजों की गुणवत्ता को उन्नत करना, बीज प्रजननशृंखला को मजबूत बनाना, बीज उत्पादन में नए टेक्नॉलोजी और तौर-तरीकों को प्रोत्साहित करना, प्रसंस्करण परीक्षण आदि को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य बीज उत्पादन भंडारण, प्रमाणीकरण तथा गुणवत्ता के लिए संरचना को मजबूत और आधुनिक बनाना है।
6. कृषि मशीनीकरण पर उपमिशन (एसएमएम) में कुल केंद्रीय हिस्सेदारी 3250 करोड़ रुपये की है। एसएमएम का उद्देश्य छोटे और मझौले किसानों तक कृषि मशीनीकरण पहुंच में वृद्धि करना, उन क्षेत्रों में कृषि मशीनीकरण बढ़ाना जहां कृषि बिजली की उपलब्धता कम है, जमीन के छोटे पट्टे और व्यक्तिगत स्वामित्व की उच्च लागत के कारण होने वाले आर्थिक नुकसानों की भरपाई के लिए 'कस्टम हायरिंग सेंटरों'को प्रोत्साहित करना, उच्च तकनीकी और उच्च मूल्य के कृषि उपकरणों का केंद्र बनाना, प्रदर्शन और क्षमता सृजन गतिविधियों के माध्यम से हितधारकों में जागरूकता कायम करना और देशभर में स्थापित निर्दिष्ट परीक्षण केंद्रों पर प्रमाणीकरण और प्रदर्शन, परीक्षण सुनिश्चित करना है।
7. पौध संरक्षण और पौधों के अलगाव पर उपमिशन (एसएमपीपीक्यू) में कुल केंद्रीय हिस्सेदारी 1022.67 करोड़ रुपये की है। एसएमपीपीक्यू का उद्देश्य कीड़े-मकोड़ों, बीमारियों, अनचाहे पौधों, छोटे कीटाणुओं और अन्य कीटाणुओं आदि से कृषि फसलों तथा उनकी गुणवत्ता को होने वाले नुकसान को कम करना है। इसका उद्देश्य बाहरी प्रजाति के कीड़े-मकोड़ों के हमलों से कृषि जैव सुरक्षा करना और विश्व बाजार में भारतीय कृषि सामग्रियों के निर्यात में सहायता करना और संरक्षण रणनीतियों के साथ श्रेष्ठ कृषि व्यवहारों को प्रोत्साहित करना है।
8. इन योजनाओं/मिशनों का फोकस उत्पादन संरचना सृजन/सुदृढ़ीकरण, उत्पादन लागत में कमी और कृषि तथा संबद्ध उत्पाद के विपणन पर है। ये योजनाएं/मिशन अलग-अलग अवधि के लिए पिछले कुछ वर्षों से क्रियान्वित की जा रही हैं।

9. इन सभी योजनाओं/मिशनो को अलग योजना/मिशन के रूप में अवगत कराया गया और स्वतंत्र रूप से स्वीकृत किया गया। वर्ष 2017-18 में यह निर्णय लिया गया है कि इन सभी योजनाओं/मिशनो को एक छतरी योजना 'हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना' के अंतर्गत लाया जाए।

15वें वित्त आयोग ने सलाहकार परिषद का गठन किया

15वें वित्त आयोग ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया है जो आयोग को परामर्श देने के साथ-साथ आवश्यक सहायता भी प्रदान करेगी। सलाहकार परिषद की भूमिका और उसके कामकाज निम्नलिखित होंगे:-

1. आयोग के विचारार्थ विषयों (टीओआर) से संबंधित विषय अथवा किसी ऐसे मसले पर आयोग को परामर्श देना जो प्रासंगिक हो सकता है।
2. एक ऐसे प्रपत्र (पेपर) अथवा अनुसंधान तैयार करने में मदद प्रदान करना जो उसके टीओआर में शामिल मुद्दों पर आयोग की समझ बढ़ाएगा।
3. वित्तीय हस्तांतरण से संबंधित विषयों पर सर्वोत्तम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं का पता लगाने और उसकी सिफारिशों की गुणवत्ता एवं पहुंच तथा अमल को बेहतर करने के लिए आयोग के दायरे एवं समझ का विस्तार करने में मदद करना।

सलाहकार परिषद में निम्नलिखित सदस्य हैं-

1. अरविंद विरमानी, अध्यक्ष, रणनीतिक पहलों के लिए फोरम
2. सुरजीत एस. भल्ला, पीएमईएसी के अंशकालिक सदस्य एवं ऑब्जर्वेटरी ग्रुप के लिए वरिष्ठ भारतीय विश्लेषक और ऑक्सस रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट्स के चेयरमैन
3. संजीव गुप्ता, पूर्व उपनिदेशक (राजकोषीय मामलों का विभाग), आईएमएफ
4. पिनाकी चक्रवर्ती, प्रोफेसर (एनआईपीएफपी)
5. श्री साजिद चिनाय, मुख्य अर्थशास्त्री भारत, जे पी मॉर्गन
6. श्री नीलकंठ मिश्रा, प्रबंध निदेशक और क्रेडिट सुईस इंडिया के अर्थशास्त्री एवं रणनीतिकार

पीएमवीवीवाई के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए निवेश सीमा बढ़ी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय समावेश और सामाजिक सुरक्षा के प्रति सरकारी प्रतिबद्धता के अंतर्गत प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) के तहत निवेश सीमा को 7.5 लाख रुपये से दोगुना कर 15 लाख रुपये करने के साथ-साथ इसकी सदस्यता की समय सीमा को 4 मई, 2018 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2020 करने की भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा पहलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मौजूदा योजना में प्रति परिवार 7.5 लाख रुपये की निवेश सीमा को बढ़ाकर संशोधित पीएमवीवीवाई में प्रति वरिष्ठ नागरिक 15 लाख रुपये कर दिया गया है। इस तरह वरिष्ठ नागरिकों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा कवर सुलभ करा दिया गया है। इससे वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह 10,000 रुपये तक पेंशन मिल सकेगी। मार्च 2018 तक कुल मिलाकर 2.23 लाख वरिष्ठ नागरिक पीएमवीवीवाई के तहत लाभान्वित हो रहे हैं। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना-2014 नामक पिछली स्कीम में कुल मिलाकर 3.11 लाख वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित हो रहे हैं।

पृष्ठभूमि

1. पीएमवीवीवाई को भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के जरिए क्रियान्वित किया जा रहा है, ताकि वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा सके और इसके साथ ही 60 साल एवं उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को अनिश्चित बाजार स्थितियों के चलते उनकी ब्याज आमदनी में किसी भी भावी कमी से उन्हें सुरक्षा प्रदान की जा सके।

2. इस स्कीम के तहत 10 साल तक प्रति वर्ष 8 प्रतिशत की गारंटीड रिटर्न दर के आधार पर एक निश्चित या आश्वासित पेंशन दी जाती है और इसमें मासिक/तिमाही/छमाही एवं वार्षिक आधार पर पेंशन का चयन करने का विकल्प दिया गया है।
3. रिटर्न में अंतर अर्थात् एलआईसी द्वारा सृजित रिटर्न और प्रति वर्ष 8 प्रतिशत के आश्वासित रिटर्न में अंतर को वार्षिक आधार पर सब्सिडी के रूप में भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला एशियाई बाजार

एशिया के बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट के टाइटल को लेकर बीते कुछ समय से जारी प्रतिस्पर्धा अब खत्म हो गई है और इस जंग में सिंगापुर के स्टॉक मार्केट को जीत हासिल हुई है। अब सिंगापुर का स्ट्रैट्स टाइम्स इंडेक्स पहले पायदान पर आ गया है और इसने वियतनाम के वीएन इंडेक्स को पछाड़ा है। साथ ही वियतनाम के इंडेक्स में दो फीसद की कमजोरी भी देखने को मिल रही है। सिंगापुर के स्ट्रैट्स टाइम्स इंडेक्स के अक्वल आने से इस देश की मुद्रा में 6.2 फीसद की बढ़त भी दर्ज की गई है।

क्या है

1. एशियाई महाद्वीप में सिंगापुर अपने तीन प्रमुख बैंकों के समर्थन के चलते सबसे बेहतर इक्विटी बाजार बना है। 30 अप्रैल को डीबीएस ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड ने तिमाही नतीजों में उम्मीद से बेहतर मुनाफा दर्ज किया है।
2. इसका प्रतिस्पर्धी यूनाइटेड ओवरसीज बैंक लिमिटेड और ओवरसी चाइनीज बैंकिंग कॉरपोरेशन रिपोर्ट आने वाले दिनों में स्ट्रैट्स टाइम्स इंडेक्स में और बढ़त दर्ज कर सकता है।
3. कोवर्नट कैपिटल टी के चीफ इवेस्टमेंट ऑफिसर एडवर्ड लिम ने कहा, “सिंगापुर का स्टॉक मार्केट उसकी ओपन इकोनॉमी को दर्शाता है।”
4. वियतनाम के इंडेक्स ने बीते वर्ष के 43 फीसद की बढ़त दर्ज की थी। वहीं 9 अप्रैल से रिकॉर्ड हाई स्तर के बाद से वीएन इंडेक्स 14 फीसद तक गिर चुका है।
5. देश के स्टॉक मार्केट वैल्यू में दो गुने से ज्यादा बढ़कर 174 बिलियन डॉलर का हो गया है। वहीं, फिलिस्तीन और इंडोनेशिया इस साल रिकॉर्ड हाई छूने के बाद से इस वक्त 2018 के सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले बाजार हैं। शांघाई और शेनजेन में चीन के स्टॉक एक्सचेंज इस साल 6 फीसद से ज्यादा की गिरावट दर्ज कर चुके हैं।

जीएसटी काउंसिल की 27वीं बैठक

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की 27वीं बैठक में 4 मई 2018 को कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में जीएसटीएन को पूरी तरह से सरकारी कंपनी बनाने के संबंध में आम सहमति बनाने के साथ-साथ सभी के लिए सिंगल मंथली रिटर्न फॉर्म पर भी एक राय बनी है। साथ ही इस बैठक में यह भी फैसला लिया गया है कि चीनी पर कोई उपकर (सेस) नहीं लगाया जाएगा।

क्या है

1. सरकारी कंपनी बनेगा **GSTN**: जीएसटी काउंसिल की 27वीं बैठक में जीएसटीएन को पूरी तरह से सरकारी कंपनी बनाने पर आम सहमति बन गई है। काउंसिल ने इस बैठक में कहा कि जीएसटीएन को सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी बनाया जाएगा। इस फैसले को विस्तार से बताते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री और जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटीएन में जो निजी कंपनियों के पास 51 फीसद की हिस्सेदारी है सरकार उसे वापस ले लेगी। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकार के पास जीएसटीएन में 50-50 फीसद की बराबर-बराबर हिस्सेदारी होगी। राज्य सरकारों के पास हिस्सेदारी प्रो-रेटा आधार पर होगी जो कि उनके जीएसटी अनुपात में होगी।

2. **चीनी पर नहीं लगेगा सेस:** जेटली ने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने सुगर पर सेस लगाने का फैसला टाल दिया गया है। काउंसिल ने गन्ना किसानों की मदद करने के लिए चीनी पर उपकर लगाने का फैसला फिलहाल के लिए टाल दिया है, क्योंकि राज्यों ने इसका विरोध किया था। वित्त मंत्री ने बताया कि किसानों की मदद करने के लिए 5 मंत्रियों की एक समिति का गठन करने का फैसला लिया गया है। यह समिति अगले दो हफ्ते में अपनी सिफारिशें देगी। इस समिति की घोषणा अगले दो दिन में कर दी जाएगी।
3. **सभी के लिए सिंगल मंथली रिटर्न फॉर्म:** काउंसिल की बैठक के बाद वित्त सचिव हसमुख अढिया ने कहा रिटर्न प्रक्रिया को और आसान बनाने और अनुपालन को बढ़ाने के लिए कारोबारियों के लिए एक सिंगल मंथली रिटर्न फॉर्म पेश किया जाएगा। हालांकि इस सिंगल मंथली रिटर्न फॉर्म को पूरी तरह से ऑपरेशनल होने में छह महीने का समय लगेगा। इसलिए तब तक मौजूदा जीएसटीआर-3बी और जीएसटीआर-1 सिस्टम को चालू रखा जाएगा।

वॉलमार्ट-फ्लिपकार्ट के बीच हुई डील

देश की ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट व दुनिया की सबसे बड़ी खुदरा कंपनी वॉलमार्ट के बीच डील हो गई है। इसकी पुष्टि सॉफ्टबैंक के सीईओ मासायोशी सन ने की है। इससे पहले संभावना जताई जा रही थी कि जल्द ही वालमार्ट और फ्लिपकार्ट के बीच अधिग्रहण का सौदा हो सकता है। यह सौदा करीब 15 अरब डॉलर का है। वालमार्ट भारतीय कंपनी में तकरीबन 70 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की बात कर रही है। वर्तमान में 30 अरब डॉलर के ई-कॉमर्स बाजार पर फ्लिपकार्ट और अमेज़न का नियंत्रण है।

क्या है

1. इस डील के बारे में कहा जा रहा था कि जापान की सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉर्प और टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट फ्लिपकार्ट में अपनी 20-20 प्रतिशत की हिस्सेदारी बेचेगी।
2. भारतीय कंपनी का मूल्य करीब 20 अरब डॉलर आंका जा सकता है। शोधकर्ता कंपनी सीबी इनसाइट्स ने पिछले साल फ्लिपकार्ट का मूल्य करीब 12 अरब डॉलर बताया था।
3. इस सौदे से वॉलमार्ट को भारत में खुदरा ऑनलाइन बाजार में अपने कदम रखने में मदद मिलेगी और वह यहां अमेज़न के मुकाबला करना चाहेगी। हालांकि, सॉफ्टबैंक के प्रवक्ता ने कहा कि वह चर्चाओं और कयासों पर कोई टिप्पणी नहीं करेगी।
4. सूत्रों ने कहा कि अमेज़न ने भी फ्लिपकार्ट में 60 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की पेशकश की थी, लेकिन कंपनी का निदेशक मंडल वालमार्ट की पेशकश के पक्ष में है।

एल्मिको और एपीसीपीएल बीच समझौता

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीनस्थ भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एल्मिको) और झज्जर स्थित अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एपीसीपीएल) ने हरियाणा के झज्जर में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एपीसीपीएल की सीएसआर पहल के तहत हरियाणा के चरखी दादरी जिले में एल्मिको के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री डी.आर.सरीन और एपीसीपीएल के सीईओ श्री एन.एन.मिश्रा की मौजूदगी में दिव्यांगों को सहायक उपकरणों और सहायक यंत्रों के वितरण हेतु 2 करोड़ रुपये की राशि दी।

क्या है

1. एल्मिको और एपीसीपीएल के बीच हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार चरखी दादरी जिले में दो करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के वितरण शिविर आयोजित किए जाएंगे।
2. इन वितरण शिविरों में कृत्रिम अंग, सहायक उपकरण जैसे मोटरयुक्त ट्राई साइकिल, व्हील चेयर, बीटीई श्रवण सहायता, दिव्यांग लोगों के लिए क्रच एक्सला समायोज्य, ब्रेल केन, एमएसआईईडी किट, ब्रेल किट, स्मार्ट केन, स्मार्ट फोन आदि वितरित किए जाएंगे।
3. एल्मिको एक गैर लाभकारी संस्था है जो कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम करने वाला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है।
4. पिछले 40 वर्षों से, एल्मिको निरंतर रूप से पीडब्ल्यूडी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरणों और सहायक यंत्रों का निर्माण कर रहा है, जिसमें हड्डी समस्याओं, दृष्टि तथा श्रवण समस्याओं को दूर करने के सहायक यंत्र शामिल हैं।
5. यह हर साल औसतन दो लाख दिव्यांग आबादी की सेवा कर रहा है और लगभग 42 लाख सहायक उपकरणों और सहायक यंत्रों की आपूर्ति करता है।
6. अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एपीसीपीएल) एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जिसमें 50 प्रतिशत हिस्सेदारी एनटीपीसी लिमिटेड, हरियाणा पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (एचपीजीसीएल, हरियाणा राज्य की कंपनी) की 25 प्रतिशत हिस्सेदारी और इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (आईपीजीसीएल, दिल्ली राज्य की कंपनी) की 25 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
7. इसने पिछले वर्ष एल्मिको के सहयोग से हरियाणा के झज्जर और रेवाड़ी जिले में दिव्यांगजन को सहायक उपकरण और सहायक यंत्र के लिए 3 करोड़ की सहायता दी और अब निकटवर्ती चरखी दादरी जिले के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

एयरटेल व टेलीनोर के विलय को मंजूरी

दूरसंचार विभाग ने टेलीनोर इंडिया व भारती एयरटेल के विलय को मंजूरी दे दी है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, 'दूरसंचार विभाग ने टेलीनोर इंडिया के भारती एयरटेल के साथ विलय को मंजूरी दी'।

क्या है

1. उच्चतम न्यायालय ने पिछले ही सप्ताह इस बारे में दूरसंचार विभाग की याचिका को खारिज करते हुए सौदे को मंजूरी देने का निर्देश दिया था।
2. विभाग चाहता था कि ये कंपनियां जमानत राशि के रूप में लगभग 1700 करोड़ रुपये जमा करवाएं।
3. इस विलय से सात सर्किलों में एयरटेल का स्पेक्ट्रम बढ़ेगा। टेलीनोर सात सर्किलों में परिचालन करती है जिनमें आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश (पूर्व व पश्चिम) तथा असम है।

विज्ञान एवं तकनीकी

नासा ने भेजा 'इनसाइट'

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का नवीनतम खोजी उपग्रह 'इनसाइट' मंगल ग्रह के अपने अभियान पर रवाना हो चुका है। लाल ग्रह पर उतरने के लिए इस उपग्रह को भेजने की प्रक्रिया नासा ने 4 मई 2018 को शुरू की थी। इस उपग्रह को मंगल की सतह पर उतरने और उस पर आने वाले भूकंप की रिकॉर्डिंग के लिए डिजाइन किया गया है। 'इनसाइट' यान कैलिफोर्निया के वांडेनबर्ग वायुसैन्य अड्डे से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक, प्रशांत क्षेत्र के समयानुसार सुबह चार बज कर पांच मिनट (भारतीय समयानुसार 4:35 बजे अपराह्न) पर एटलस वी. रॉकेट से लांच किया जाना था। वैज्ञानिक चिंतित थे कि अगर लांच किए जाने से पहले आसमान में धुंध हुई तो प्रक्षेपण में तकनीकी स्तर पर समस्याएं हो सकती हैं। नासा के सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि दृश्यता में बाधा खत्म हो गई इसलिए लांच की प्रक्रिया शुरू की गई।

क्या है

1. इस महत्वाकांक्षी परियोजना का मकसद मंगल ग्रह के जमीनी हालात का पता लगाना है। इससे मिली जानकारियां भविष्य में वहां मानवयुक्त अंतरिक्ष यान को भेजने में मददगार हो सकती हैं।
2. इससे यह पता लगाने में भी मदद मिलेगी कि अरबों साल पहले कैसे वह धरती की तरह चट्टानी ग्रह में तब्दील हुआ। नासा के अधिकारियों ने कहा, योजना के मुताबिक सब कुछ

फ्लैश पवॉइंट

1. 99.3 करोड़ डॉलर की है 'इनसाइट' उपग्रह की यह परियोजना
2. 26 नवंबर तक मंगल पर पहुंच कर काम शुरू करने की उम्मीद
3. 26 माह या मंगल के एक वर्ष तक कार्य करने में सक्षम है यह यान
4. 100 भूकंपों को दर्ज कर सकेगा यह मंगल पर रहने के दौरान
5. 20 डिग्री सेल्सियस रहता है तापमान मंगल का गर्मियों के दिनों में
6. 73 डिग्री सेल्सियस हो जाता है यह उन्हीं दिनों रात के दौरान
7. 2016 में लांच किया जाना था पहले, पर इसके भूकंपमापी में समस्या का पता चलने पर समय बढ़ाना पड़ा
8. 2012 में भेजे गए क्यूरिओसिटी रोवर के बाद मंगल ग्रह पर जाने वाला नासा का दूसरा यान होगा 'इनसाइट'
9. 2030 तक मंगल ग्रह पर मानवयुक्त अभियान भेजने की योजना है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी की

ठीक रहा तो 'इनसाइट' मंगल ग्रह पर 26 नवंबर तक कामकाज करना शुरू कर देगा।

3. इस खोजी यान का पूरा नाम 'इंटरियर एक्सप्लोरेशन यूजिंग सिस्मिक इन्वेस्टिगेशंस, जियोडेसी एंड हीट ट्रांसपोर्ट' है।
4. नासा के प्रधान वैज्ञानिक जिम ग्रीन ने कहा, विशेषज्ञों को पहले से पता है कि मंगल पर भूकंप, भूस्खलन और उल्कापात होते हैं। लेकिन हमें इस ग्रह के लिए संभावित मानव अभियानों के लिए यह जानना जरूरी है कि मंगल भूकंप के लिहाज से कितना संवेदनशील है। इनसाइट मंगल ग्रह पर जाकर इस सवाल का जवाब खोजेगा। इसकी सतह पर एक भूकंपमापी लगा है।
5. मंगल पर पहुंचने के बाद उपग्रह की एक रोबोटिक बांह इसमें लगे भूकंपमापी को सतह पर स्थापित करेगी। इसके बाद उपग्रह मंगल की सतह पर 10 से 16 फीट गहरी खुदाई कर एक स्वचालित जांच करेगा, जिससे ग्रह की सतह पर उष्मा के प्रवाह की जानकारी हो सकेगी। यह अभी तक के मंगल अभियानों के तहत इस ग्रह की सतह पर की गई खुदाई से 15 गुना अधिक होगा।

चंद्रमा पर पानी मौजूद होने के मिले संकेत

वैज्ञानिकों को एक चंद्र उल्कापिंड में एक ऐसा खनिज मिला है जो चंद्रमा के सतह के नीचे बर्फ के रूप में बड़ी मात्रा में पानी के मौजूद होने का संकेत देता है जो कि भविष्य के मानव अन्वेषण के लिए काफी सहायक हो

सकता है। जापान के तोहोकू विश्वविद्यालय के एक दल को उत्तर पश्चिम अफ्रीका में एक रेगिस्तान में मिले एक चंद्र उल्कापिंड में मोगेनाइट नाम का एक खनिज मिला है।

क्या है

1. मोगेनाइट सिलिकॉन डायआक्साइड का क्रिस्टल होता है जो कि पृथ्वी पर विशिष्ट अवसादी परिस्थितियों में क्षारीय तरल पदार्थ से बनता है। यह खनिज इससे पहले चंद्रमा के पत्थरों में नहीं मिला है।
2. अनुसंधानकर्ताओं का मानना है कि यह खनिज चंद्रमा के सतह पर 'प्रोसेलेरम टेरेन' नामक क्षेत्र में बना है क्योंकि चंद्रमा की धूल में मूल रूप से मौजूद पानी कड़ी धूप से वाष्प बनकर उड़ गया।
3. इस अध्ययन का नेतृत्व करने वाले तोहोकू विश्वविद्यालय के मासाहिरो कायामा ने कहा कि पहली बार हम यह साबित कर सकते हैं कि चंद्र के द्रव्य में बर्फ के रूप में पानी है।

ट्राइफेड डिजिटल हुआ

जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) ने देशभर के अपने सभी अपने बिक्री केंद्रों, क्षेत्रीय कार्यालयों और मुख्य कार्यालयों को डिजिटल प्रणाली से जोड़ दिया है और तैयार माल के स्टॉक (इन्वेंट्री) के लिए रिटेल इन्वेंट्री साफ्टवेयर का प्रयोग शुरू कर दिया है।

क्या है

1. अब इसके सभी केंद्रों पर बिक्री सहित समस्त लेखाजोखा डिजिटल तरीके से होगा, ताकि पारदर्शिता के साथ-साथ समस्त लेनदेन की निगरानी की जा सके।
2. रिटेल इन्वेंटरी साफ्टवेयर (आरआईएस) में खुदरा बिक्री प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में विक्रेता के लिए वस्तु चयन, चयनित वस्तुओं के लिए कोड जनरेशन के लिए अनुरोध, खरीद अनुरोध, स्टॉक और पीओएस तथा सूची प्रबंधन के माध्यम से सूची विवरण की निगरानी शामिल है।
3. इसके जरिए क्षेत्रीय कार्यालय में बिक्री/खरीद की रिपोर्ट प्रमुख कार्यालय को भेजी जा सकेगी।

रोबोट ने की पहली सर्जरी

भारतीय मूल के एक सर्जन की अगुवाई में विश्व में रोबोट के जरिए पहली सर्जरी की गई। इसमें एक मरीज की गर्दन से दुर्लभ किस्म के ट्यूमर को सफलतापूर्वक निकाला गया। कॉर्डोमा कैंसर का एक दुर्लभ प्रकार है जो खोपड़ी और रीढ़ की हड्डी में होता है। कॉर्डोमा का ट्यूमर बहुत धीरे-धीरे गंभीर रूप अख्तियार करता है और कई वर्षों तक इसका कोई लक्षण देखने को नहीं मिलता।

क्या है

1. अमेरिका के 27 वर्षीय नोआ पर्निकॉफ 2016 में एक कार हादसे में जख्मी हो गए थे। मामूली चोट से उबरने के बाद उनके गर्दन में काफी दर्द होने लगा था। इसके बाद एक्सरे कराया गया, जिसमें उसके गर्दन में चिंतनीय क्षति का पता चला।
2. ये जख्म दुर्घटना से संबंधित नहीं थे और उन्हें लगी चोट की तुलना में बहुत अधिक चिंता पैदा करने वाले थे। इसके बाद उस स्थान की बायोप्सी की गयी। इसमें व्यक्ति के कॉर्डोमा से पीड़ित होने की बात निकलकर सामने आई।
3. कॉर्डोमा काफी दुर्लभ है। हर साल दस लाख लोगों में कोई एक इससे प्रभावित होता है। पर्निकॉफ के मामले में कॉर्डोमा सी 2 कशेरुका में था। यह और भी दुर्लभ है और इसका उपचार चुनौतीपूर्ण होता है।
4. पर्निकॉफ की सर्जरी तीन चरणों में हुई। पहले दौर में न्यूरोसर्जन ने मरीज के गर्दन के पिछले हिस्से में ट्यूमर के पास रीढ़ की हड्डी को काट दिया ताकि दूसरे चरण में ट्यूमर को मुंह से निकाला जा सके।

5. पहले चरण की सफलता के बाद सर्जिकल रोबोट के इस्तेमाल के जरिये डॉक्टरों की टीम ने उसके गर्दन से मुंह तक के हिस्से को साफ किया ताकि मल्होत्रा ट्यूमर और रीढ़ की हड्डी के हिस्से को निकाल सकें। अंतिम चरण में टीम ने पर्निकॉफ की रीढ़ की हड्डी को उसके पूर्व के स्थान पर फिट किया। सर्जरी के नौ माह बाद पर्निकॉफ काम पर लौट चुके हैं।

पीसा की झुकी हुई मीनारों का रहस्य खुला

पीसा की झूलती हुई मीनारें हमेशा से दुनियाभर के वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बनी हुई थीं। अब शोधकर्ताओं ने इस रहस्य से पर्दा उठाने का दावा किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल के 16 इंजीनियरों की टीम ने पीसा की झुकी हुई मीनारों की पड़ताल की। इस दल में एक प्रमुख भूकंप विशेषज्ञ और मिट्टी की संरचना के विशेषज्ञ भी शामिल थे। ब्रिस्टल के डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर जॉर्ज मिलोनाकिस और रोमा त्रे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कैमिलो न्यूटी को भी इस दल में शामिल होने के लिए आतंत्रित किया गया था।

क्या है

1. तकरीबन पांच डिग्री पर झूल रही 58 मीटर ऊंची इन मीनारों ने क्षेत्र में 1280 से आगे कम से कम चार जबरदस्त भूकंप भी झेले हैं। इन ढांचों को देखकर हमेशा यही खतरा बना रहा कि यह मामूली भूकंपीय हरकत से गिर सकती हैं, मगर ऐसा हुआ नहीं। यही रहस्य वैज्ञानिकों के लिए खोज का सबब बना हुआ था।
2. इस क्षेत्र की भूकंपीय गतिविधियों, जियोटेक्निकल और संरचना संबंधी जानकारी का अध्ययन करने के बाद शोध टीम ने कहा कि इन मीनारों के वजूद के लिए डायनेमिक स्ट्रक्चर इनटरएक्शन (डीएसएसआई) जिम्मेदार है।
3. मीनारों के नीचे की मिट्टी और उसकी ऊंचाई व कड़ापन के कारण इस संरचना में भूकंप झेलने की इतनी जबरदस्त क्षमता है। यह मीनारें जिस जमीन पर खड़ी हैं, वहां भूकंप आने पर इसकी संरचना की कंपन को बर्दाश्त करने की क्षमता के कारण इनको कोई नुकसान नहीं हुआ।
4. इस अध्ययन के नतीजे अगले माह यूनान में होने वाली 16वीं यूरोपियन कॉन्फ्रेंस इन अर्थक्वैक इंजीनियरिंग में औपचारिक रूप से घोषित किए जाएंगे।

चीन में मिला द्वितीय विश्व युद्ध का बम

चीन के शहर हांगकांग में एक निर्माणाधीन मेट्रो स्टेशन के पास द्वितीय विश्व युद्ध का बम मिला है। यह बम करीब 450 किलोग्राम भारी है। इस बम के मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने इस इलाके से कम से कम 1200 लोगों को खाली करवाया। पुलिस के मुताबिक बम निरोधक दस्ता ने 450 किलोग्राम (1,000 पौंड) वजन के बम को निष्क्रिय किया, जो कि अमेरिका का बना हुआ बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक, इस साल अब तक तीन इस तरह के बमों का पता लगाया गया है।

क्या है

1. पुलिस ने 20 घंटे की मेहनत के बाद इस बम को निष्क्रिय कर दिया। बम निरोधक दस्ते का कहना था कि उन्हें बम को निष्क्रिय करने में बेहद सावधानी बरतनी पड़ी, क्योंकि यह बम जमीन में सीधा खड़ा हुआ था। जिसकी वजह से इसका आधा हिस्सा जमीन के अंदर धसा हुआ था।
2. बताया जाता है कि 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने हांगकांग पर भारी हमला किया था। 2016 में भी इसी इलाके में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वाले छः अनदेखे ग्रेनेड और दो मोर्टार गोले पाए गए थे।

3. इसके अलावा पुलिस ने 2014 में लगभग एक टन वजन वाले युद्धक बम को निष्क्रिय किया था, जो शहर में पाया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा बम था।

अब ई-वेस्ट से निकाले जा सकेंगे सोना और प्लैटिनम

अब कबाड़ से सोना और कीमती धातु प्लैटिनम निकाले जाएंगे। 1000 किलो इलेक्ट्रॉनिक कबाड़ (ई-वेस्ट) से 300 ग्राम तक सोना, प्लैटिनम, पैलेडियम और चांदी निकलेगी। जमशेदपुर की एनएमएल (नेशनल मेटलर्जिकल लैबोरेटरी) के प्रधान वैज्ञानिक मनीष झा ने कई साल के शोध के बाद यह तकनीक विकसित की है। इलेक्ट्रॉनिक कबाड़ से सोना निकालने के लिए केमिकल प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रोलाइसिस व इलेक्ट्रो प्लेटिंग की विधि अपनाई जाती है। प्रधान वैज्ञानिक ने इस तकनीक का सफल प्रयोग कर लिया है।

क्या है

1. ई-वेस्ट बेहद खतरनाक माना जाता है। इसे बाहर फेंक देने से पर्यावरण पर इसका बुरा असर पड़ता है। इससे लोगों में तरह-तरह की बीमारी होती है। ई-वेस्ट के असर से लोग मानसिक रोगी हो जाते हैं। किडनी और लिवर भी फेल हो जाते हैं।
2. ई-वेस्ट को रिसाइकिल कर देने से इसमें मौजूद जहरीले रसायन खत्म हो जाते हैं। यही नहीं, इनमें मौजूद कीमती धातुओं को बाहर निकाल लिया जाता है।
3. टीवी, मोबाइल आदि इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में सर्किट बोर्ड और मदर बोर्ड में कीमती धातुओं का इस्तेमाल होता है। प्लैटिनम और सोने का जितना ज्यादा प्रयोग इसमें होगा, उतना ही उस यंत्र का साउंड सिस्टम अच्छा होता है। इसलिए महंगे इलेक्ट्रॉनिक सामानों से ज्यादा मात्रा में सोना निकलता है।
4. मनीष झा विश्व रिसाइकिलिंग स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य हैं। उन्होंने ई वेस्ट पर काफी काम किया है। इसे लेकर होने वाले सेमिनार में शिरकत करने वे यूरोप के कई देशों के अलावा, जर्मनी, जापान और दक्षिण कोरिया भी जा चुके हैं। उन्होंने रिसाइकिलिंग के कई फायदे बताए हैं।
5. ई-वेस्ट से हर धातु निकालने की तकनीक अलग है। एल्यूमिनियम से सोना निकालने, तांबा से सोना निकालने व लोहे से सोना निकालने की अलग-अलग विधि है।
6. प्रधान वैज्ञानिक मनीष झा बताते हैं कि अगर ई-वेस्ट में एल्यूमिनियम से सोना निकालना है तो इसके केमिकल प्रोसेसिंग में सल्फ्यूरिक एसिड, अलकली, सोडियम हाइड्रेड आदि का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह प्लैटिनम, पैलेडियम और चांदी निकालने के लिए केमिकल प्रोसेसिंग में अलग रसायनों का प्रयोग किया जाता है।
7. ई-वेस्ट से सोना, प्लैटिनम जैसी धातु निकालने की तकनीक बेहद उपयोगी है। इससे जहां एक तरफ ई कचरा के खपने से पर्यावरण प्रदूषण खत्म होगा, वहीं इससे निकली कीमती धातु बेचकर लाखों कमाया जा सकता है। इसके लिए यह तकनीक काफी मददगार साबित होगी। भविष्य में ई-कबाड़ बढ़ेगी और लोग इसका फायदा ले सकेंगे। भविष्य के लिए यह तकनीक वरदान है।

विविध

विश्व मजदूर दिवस

1 मई को पूरी दुनिया में विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। कई जगह इसे मई दिवस भी कहा जाता है। कई देशों में इस दिन सार्वजनिक अवकाश होता है। भारत में इसे अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस या कामगार दिवस मनाया जाता है।

क्या है

1. पूरी दुनिया में मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत 1 मई 1886 को हुई।

2. जब अमेरीका में मजदूर संघ ने काम का समय 8 घंटे से ज्यादा न रखे जाने के लिए बड़ी हड़ताल रैली की।
3. भारत में 1923 में पहली बार मजदूर दिवस मनाया गया।
4. पहली बार लेबर किसान पार्टी ने चेन्नई में मई दिवस का आयोजन कराया।

दुनिया भर में दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर

देश की राजधानी दिल्ली को एक बार फिर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शामिल किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने दुनिया भर के 14 मिलियन यानी 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में प्रदूषण के स्तर की एक लिस्ट जारी की है। उनकी इस रिपोर्ट में दिल्ली को पहला वहीं भारत की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले मुंबई को चौथा स्थान मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक मिस्त्र का ग्रेटर कायरो दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है, जबकि बांग्लादेश की राजधानी ढाका तीसरे और चीन की राजधानी बीजिंग पांचवे नंबर पर है।

क्या है

1. डब्ल्यूएचओ ने वायु गुणवत्ता आंकड़ों पर आधारित अपनी रिपोर्ट में बताया है कि दुनिया भर के 90 फीसदी लोग प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं। इसकी वजह से 2016 में 70 लाख (7 मिलियन) लोगों की मौत हुई थी।
2. इसमें ये भी बताया गया है कि 2016 में दुनिया भर में उद्योगों से निकलने वाले धुएं, ट्रक और कार से निकलने वाले धुएं की वजह से जो वायु प्रदूषित होती है उससे करीब 4.2 मिलियन यानी 42 लाख लोगों की मौत हुई थी। वहीं इंडोर यानी घर के अंदर मौजूद प्रदूषण के कारण के कारण 3.8 मिलियन यानी 38 लाख लोगों की मौत हुई थी।
3. भारत परिवेश और इनडोर वायु प्रदूषण के दोहरे बोझ के वजन के नीचे भी पीड़ित है। विश्लेषण से पता चलता है कि भारत के कई छोटे कस्बों और शहरों में दिल्ली के मुकाबले प्रदूषण के स्तर की भी रिपोर्ट है; दिल्ली की आबादी, 17 मिलियन से अधिक लोगों का घर, वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य प्रभाव को जोड़ती है।
4. दुनिया के 15 प्रदूषित शहरों में भारत के 14 शामिल नामों में, कानपुर पहले और पटना 5वें नंबर पर है।
5. रिपोर्ट से इस बात का भी पता चलता है कि भारत सिर्फ भार की वजह से नहीं बल्कि बाहरी और भीतरी प्रदूषण से भी जूझ रहा है। विश्लेषण से पता चलता है कि भारत के कई छोटे शहरों में भी प्रदूषण का स्तर दिल्ली के मुकाबले कम नहीं है। प्रदूषण के खिलाफ सरकार और न्यायपालिका के जबर्दस्त प्रयास के बावजूद भारत में प्रदूषण का स्तर कम नहीं हो रहा है। अप्रैल 2020 से भारत में भारत स्टेजपट की गाड़ियां आने वाली है।

भारत में सबसे प्रदूषित कौन

1. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने 15 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची जारी की है। इस लिस्ट में 14 नाम भारतीय शहरों के हैं, जिसमें कानपुर टॉप पर, वाराणसी तीसरे नंबर और पटना पांचवें नंबर पर है। वहीं दिल्ली का स्थान इस सूची में छठे नंबर पर है। प्रदूषित शहरों की यह लिस्ट 2016 की है। WHO के डेटाबेस से पता चलता

टॉप 15 शहर

1. कानपुर (173 माइक्रोग्राम/ क्यूबिक मीटर)
2. फरीदाबाद (172 माइक्रोग्राम/ क्यूबिक मीटर)
3. वाराणसी (151 माइक्रोग्राम/ क्यूबिक मीटर)
4. गया (149 माइक्रोग्राम/ क्यूबिक मीटर)
5. पटना (144 माइक्रोग्राम/ क्यूबिक मीटर)
6. दिल्ली (143 माइक्रोग्राम/ क्यूबिक मीटर)
7. लखनऊ (138 माइक्रोग्राम/ क्यूबिक मीटर)
8. आगरा (131 माइक्रोग्राम/ क्यूबिक मीटर)
9. मुजफ्फरपुर (120 माइक्रोग्राम/ क्यूबिक मीटर)
10. श्रीनगर (113 माइक्रोग्राम/ क्यूबिक मीटर)
11. गुरुग्राम (113 माइक्रोग्राम/ क्यूबिक मीटर)
12. जयपुर (105 माइक्रोग्राम/ क्यूबिक मीटर)
13. पटियाला (101 माइक्रोग्राम/ क्यूबिक मीटर)
14. जोधपुर (98 माइक्रोग्राम/ क्यूबिक मीटर)
15. अली सुबाह अल सलीम (कुवैत) (94 माइक्रोग्राम/ क्यूबिक मीटर)

है कि 2010 से 2014 के बीच में दिल्ली के प्रदूषण स्तर में मामूली बेहतरी हुई है लेकिन 2015 से फिर हालत बिगड़ने लगे है।

- 2.5 पीएम (फाइन पार्टिकुलर मैटर) को ध्यान में रखते हुए प्रदूषण पर 100 देशों के 4000 शहरों में रिसर्च के बाद ये आंकड़े सामने आए हैं। आपको बता दें कि 2010 में WHO ने प्रदूषित शहरों की सूची जारी की थी तो दिल्ली टॉप पर था। दूसरे और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान के पेशावर और रावलपिंडी शहर था। इस बार टॉप 15 शहरों में पाकिस्तान और चीन का कोई शहर शामिल नहीं है।

सेना पर खर्च करने वाले शीर्ष पांच देशों में है भारत

साल 2017 में सेना पर खर्च के मामले में भारत और चीन दुनिया के शीर्ष पांच देशों में शामिल हैं। दोनों देशों का रक्षा खर्च कुल मिलाकर वैश्विक रक्षा खर्च का 60 फीसद रहा। वैश्विक रक्षा खर्च 2016 के मुकाबले 1.1 फीसद वृद्धि के साथ 1.739 ट्रिलियन डॉलर हो गया। स्वीडन की स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (सिपरी) की रिपोर्ट के मुताबिक, रक्षा खर्च के मामले में शीर्ष पांच देश अमेरिका, चीन, सऊदी अरब, रूस और भारत रहे।

क्या है

1. रिपोर्ट के मुताबिक, चीन करीब दो दशकों से रक्षा खर्च में बढ़ोतरी कर रहा है। 2017 में उसका सैन्य खर्च 228 अरब डॉलर रहा। यह एशिया और ओशनिया क्षेत्र के कुल रक्षा खर्च का 48 फीसद है।
2. यह भारत के रक्षा खर्च से 3.6 गुना ज्यादा है। भारत ने सेना पर 63.9 अरब डॉलर खर्च किए। 2016 के मुकाबले इसमें 5.5 फीसद और 2008 के बाद से 45 फीसद की वृद्धि हुई।
3. रिपोर्ट के मुताबिक, 610 अरब डॉलर रक्षा खर्च के साथ अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा। उसका रक्षा खर्च दूसरे स्थान पर रहने वाले चीन के रक्षा खर्च से 2.7 गुना ज्यादा है।
4. सिपरी के मुताबिक, 2016 और 2017 के बीच अमेरिका के सैन्य खर्च में कोई बदलाव नहीं हुआ। दूसरी तरफ रूस का सैन्य खर्च 1998 के बाद से पहली बार कम हुआ। 2017 में यह 66.3 अरब डॉलर रहा। यह 2016 की तुलना में 20 फीसद कम है।
5. रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस से बढ़ते खतरे की आशंका से मध्य और पश्चिमी यूरोप के सैन्य खर्च में 2017 में क्रमशः 12 और 1.7 फीसद की वृद्धि हुई।
6. रिपोर्ट के मुताबिक, नाटो के सभी 29 सदस्य देशों का कुल रक्षा खर्च 900 अरब डॉलर रहा। यह वैश्विक रक्षा खर्च का 52 फीसद है। 2017 में कुल वैश्विक रक्षा खर्च वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 2.2 फीसद रहा।

विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस

प्रत्येक वर्ष 3 मई को अंतरराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाना है। इसकी शुरुआत 1993 में हुई थी, जिसका मकसद था दुनियाभर में स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन करना और उसकी रक्षा करना। प्रेस किसी भी समाज का आइना होता है। प्रेस की आजादी से यह बात साबित होती है कि उस देश में अभिव्यक्ति की कितनी स्वतंत्रता है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में प्रेस की स्वतंत्रता एक मौलिक जरूरत है।

क्या है

1. विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा, स्वतंत्र प्रेस एक मजबूत लोकतंत्र बनाता है।
2. आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम एक स्वतंत्र प्रेस का समर्थन करने के लिए अपनी वचनबद्धता दर्शाएँ। यह विचारों और मानव अभिव्यक्ति की बहुलता है जो हमें समाज के रूप में अधिक जीवंत बनाता है।

3. यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस के सुझाव के बाद 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी शुरुआत की, जिसके बाद से हर साल 3 मई को अंतरराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा।
4. यूनेस्को महासम्मेलन के 26वें सत्र में इससे संबंधित प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। इससे पहले नामीबिया में विंडहोक में हुए एक सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया गया था कि प्रेस की आजादी को मुख्य रूप से बहुवाद और जनसंचार की आजादी की जरूरत के रूप में देखा जाना चाहिए।
5. अंतरराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रेस की स्वतंत्रता का मूल्यांकन, प्रेस की स्वतंत्रता पर बाहरी तत्वों के हमले से बचाव और प्रेस की सेवा करते हुए दिवंगत हुए पत्रकारों को श्रद्धांजलि देने का दिन है। आज उन पत्रकारों को याद किया गया, जिन्होंने अपना फर्ज निभाते हुए जान तक दे दी, लेकिन लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की गरिमा को मरते दम तक निभाया।

डीएसटी ने अपना संस्थापना दिवस मनाया

केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने 3 मई 2018 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के नये अत्याधुनिक भवन का शिलान्यास किया। नये अत्याधुनिक भवन के बारे में संक्षिप्त जानकारी देते हुए डीएसटी के सचिव प्रो. आशुतोष शर्मा ने कहा कि इरकॉन ने परियोजना का पहला चरण 15 महीनों के भीतर पूरा करने का वायदा किया है। प्रो. शर्मा ने श्रोताओं से नये विचार साझा करने की अपील की, जिससे नये भवन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अनूठे तत्वों को शामिल किया जा सके। डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि 'नये अत्याधुनिक भवन का निर्माण 3 मई, 2021 तक पूरा हो जाना चाहिए, जब डीएसटी अपना स्वर्ण जयंती मनाएगा।

क्या है

1. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तीन विभागों में से एक, डीएसटी की स्थापना 3 मई, 1971 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नये क्षेत्रों की खोज करने तथा विकास के लिए उद्देश्य को अभिव्यक्त करने, राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षमता को सुदृढ़ बनाने एवं सभी संस्थानों और विषयों की क्षमता बढ़ाने के लिए की गई थी।
2. प्रौद्योगिकी भवन के रूप में लोकप्रिय, वर्तमान डीएसटी परिसर की स्थापना और उपयोग पीएल-480 'पब्लिक लॉ-480' के तहत अमेरिकी सहायता एजेंसी द्वारा खाद्यान्नों के भंडारण के लिए किया गया था।
3. स्वच्छ भारत अभियान के एक हिस्से के रूप में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में 01 मई, 2018 से 15 मई, 2018 तक स्वच्छता पखवाड़े का भी आयोजन किया जा रहा है।
4. डीएसपी प्रत्येक वर्ष 3 मई को अपना संस्थापना दिवस मनाता है, जो इस वर्ष स्वच्छता पखवाड़े के दौरान आयोजित किया जा रहा है। पखवाड़े के दौरान अन्य कार्यक्रमों के अतिरिक्त, डीएसटी के लिए चुनौतियां एवं हितधारकों से अपेक्षाएं विषय पर एक गोलमेज परिचर्चा का भी आयोजन किया। डीएसटी के विख्यात पूर्व सचिवों, विख्यात वैज्ञानिकों, सीनियर फेलो जैसे विभिन्न हितधारकों एवं मीडिया से जुड़े व्यक्तियों ने भी परिचर्चा में भाग लिया।
5. स्वच्छता पखवाड़े के दौरान जिन अन्य कार्यक्रमों की योजना बनाई गई, उनमें स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु, स्वच्छ ऊर्जा एवं अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेषज्ञों की वार्ताएं एवं हितधारकों के परामर्श शामिल थे। डीएसटी कई वर्षों से इन क्षेत्रों में अनुसंधान परियोजनाओं का वित्त पोषण करता रहा है।
6. पखवाड़े के दौरान डीएसटी के समर्थन से विकसित प्रौद्योगिकियों पर वैज्ञानिकों एवं विशेषज्ञों द्वारा चर्चा की जाएगी। इन प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रदर्शनी का आयोजन प्रौद्योगिकी भवन परिसर में 7 मई से 10 मई 2018 तक तथा 11 मई को विज्ञान भवन में किया जाएगा, जहां राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का समारोह मनाया जाएगा।

इस बार नहीं दिया जाएगा साहित्य का नोबेल पुरस्कार

इस साल साहित्य में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। दरअसल, नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था सेक्स स्कैंडल में फंस गई है जिसके बाद 2018 में साहित्य का नोबेल प्रदान करने का निर्णय टाल दिया गया। फ्रेंच फोटोग्राफर जीन क्लाउड अरनॉल्ट के कथित यौन दुराचार को लेकर स्वीडिश एकेडमी आलोचनाओं के घेरे में है। अरनॉल्ट की शादी सदियों पुरानी एकेडमी के एक पूर्व सदस्य के साथ हुई है।

क्या है

1. एकेडमी को यह फैसला करना है कि क्या इस साल यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा क्योंकि एकेडमी के कुछ सदस्य यह पुरस्कार प्रदान करने को लेकर चिंतित हैं और वे इसके लिए स्थिति को अनुकूल नहीं बता रहे हैं।
2. पिछले साल नवंबर में 18 महिलाओं ने 'हैश मी टू' आंदोलन के माध्यम से अरनॉल्ट पर यौन हमला व उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। एकेडमी की परिसंपत्ति को लेकर भी कथित तौर पर कई आरोप लगाए गए हैं। अरनॉल्ट ने सभी आरोपों से इनकार किया है।
3. संगठन ने उनकी पत्नी और कवयित्री व लेखिका कटरीना फ्रोस्टेनसन को 18 सदस्यीय कमेटी से निकालने को लेकर वोट किया।
4. इसके अगले दिन एकेडमी की स्थायी सदस्य सारा डेनिअस ने कहा कि संस्थान ने कथित आरोपों के बाद अरनॉल्ट से पूरी तरह संबंध तोड़ लिया है। उनपर एकेडमी के कर्मचारी व सदस्यों के रिश्तेदारों के साथ अवांछित यौन संबंध बनाने के आरोप हैं। डेनिअस समेत अब तक एकेडमी के छह सदस्यों ने अपना इस्तीफा दे दिया है।
5. इससे पहले 1943 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार द्वितीय विश्व युद्ध को लेकर स्थगित कर दिया गया था।

महान विचारक कार्ल मार्क्स का 200वां जन्मदिन

जर्मनी के महान विचारक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांतकार, समाजशास्त्री, पत्रकार और क्रांतिकारी कार्ल मार्क्स का आज यानी पांच मई को 200वां जन्मदिन है। 1848 में उन्होंने अपने साथी फ्रेडरिक एंजेल्स के साथ मिलकर द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जारी किया। इसमें उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में मार्क्सवादी व्यवस्था की अवधारणा लोगों के सामने रखी। 1917 में जिस रूसी क्रांति ने तीन सदी से चले आ रहे जार साम्राज्य को खत्म करके सर्वहारा सत्ता की नींव रखी, वह कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर आधारित थी।

क्या है

1. जर्मन राजमंडल में प्रशिया साम्राज्य के ट्रियर शहर में वकील हीनरिक मार्क्स और हेनरीटा प्रेसबर्ग के घर पांच मई, 1818 को कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ। उनके माता-पिता यहूदी थे। बाद में वकालत जारी रखने के लिए उन्होंने 1816 में यहूदी धर्म छोड़कर ईसाई धर्म की प्रमुख शाखा कहे जाने वाले लूथरानिज्म धर्म को अपना लिया।
2. छह वर्ष की उम्र में कार्ल मार्क्स को भी ईसाई धर्म में शामिल किया गया। बाद में वह नास्तिक बन गए।
3. 1835 में 17 वर्ष की उम्र में मार्क्स ने दर्शनशास्त्र और साहित्य पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन में दाखिला लिया।
4. डिग्री पूरी होने के बाद उन्होंने उदारवादी लोकतांत्रिक समाचार पत्र रिनीश्चे जिटुंग के लिए लिखना शुरू किया।
5. 1842 में अखबार के संपादक हो गए। सरकार ने उनके अखबार को अत्यधिक स्वच्छंद मानते हुए प्रतिबंधित कर दिया।
6. 1843 में अपनी पत्नी जेनी बॉन वेस्टफैलेन के साथ पेरिस आ गए। यहां उनकी मुलाकात साथी जर्मन प्रवासी फ्रेडरिक एंजेल्स से हुई।
7. 1864 में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय श्रमिक सभा का गठन किया। तीन वर्ष बाद उन्होंने दास कैपिटल किताब का पहला संस्करण प्रकाशित कराया। इसे आर्थिक सिद्धांतों पर उनका सबसे बेहतरीन काम माना जाता है। इसमें उन्होंने सिद्धांत दिया कि पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था है जो अपने विनाश और मार्क्सवाद की जीत के बीज अपने अंदर पाले हुए हैं।

फिर भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ 'डकोटा विमान'

हिंडन एयर फोर्स स्टेशन पर 4 मई 2018 को आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में नवीनीकृत डकोटा विमान को औपचारिक रूप से भारतीय वायु सेना में शामिल कर लिया गया। इस विमान को चार दशक से भी ज्यादा समय पहले वायु सेना से सेवानिवृत्त कर दिया गया था। इसे अब नया नाम 'परशुराम' दिया गया है। राज्यसभा सदस्य राजीव चंद्रशेखर ने इस डकोटा डीसी-3 वीपी-905 विमान को कबाड़ से खरीदकर ब्रिटेन में नवीनीकृत कराया है। कार्यक्रम में राजीव चंद्रशेखर के पिता एयर कोमोडोर (सेवानिवृत्त) एमके चंद्रशेखर के हाथों चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल बीएस धनोआ ने विमान की चाबियां ग्रहण कीं। इस मौके पर धनोआ ने डकोटा को भारतीय वायु सेना के इतिहास का विशेष विमान बताते हुए कहा कि ब्रिटेन से भारत की यात्रा ने इस विमान की विश्वसनीयता और मजबूती को साबित कर दिया है।

क्या है

1. विमान ने 17 अप्रैल को ब्रिटेन से भारत के लिए अपनी यात्रा शुरू की थी। इसके चालक दल में भारतीय वायु सेना के अलावा 'रीफ्लाइट एयरवर्क्स' के सदस्य भी शामिल थे।
2. 9,750 किमी की यात्रा में इस विमान ने फ्रांस, इटली, ग्रीस, जॉर्डन, बहरीन व ओमान में ठहराव लिया और 25 अप्रैल को जामनगर स्थित एयर फोर्स स्टेशन पहुंचा। रक्षा मंत्री की विशेष अनुमति से एयर कमांडर (सेवानिवृत्त) एम.के. चंद्रशेखर ने भी 26 अप्रैल को जामनगर से हिंडन एयर फोर्स स्टेशन तक इस विमान में यात्रा की।
3. परिवहन विमान (कार्गो प्लेन) डकोटा को 1930 में रॉयल इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया था। इसने द्वितीय विश्वयुद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
4. वर्ष 1947 और 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध में भी इसने अहम भूमिका अदा की थी। 1947 के युद्ध में भारत की जीत और कश्मीर की सुरक्षा में इसका योगदान अद्वितीय था। युद्ध के दौरान यह सेना की एक टुकड़ी को जम्मू-कश्मीर लेकर गया, जिसने पुंछ से हमलावरों को खदेड़ दिया।
5. वायुसेना अधिकारियों के अनुसार डकोटा पूरी तरह कबाड़ हो चुका था। इसकी मरम्मत के लिए इसे ब्रिटेन भेजा गया। जहां करीब छह साल तक इसकी मरम्मत होती रही और इसका सारा खर्च उठाया राज्यसभा सदस्य राजीव चंद्रशेखर ने। इसके बाद उन्होंने इसे वायुसेना को भेंट किया है। राजीव के पिता एयर कमांडर एम.के. चंद्रशेखर डकोटा के पायलट थे। अधिकारियों के मुताबिक डकोटा का नंबर अब भी वीपी 905 होगा जो 1947 के युद्ध में जम्मू-कश्मीर भेजे गए पहले डकोटा विमान का भी नंबर था।

विमान की मुख्य विशेषताएं

1. 21-32 यात्रियों की क्षमता
2. 64 .8 फीट (19.7 मीटर) लंबाई
3. 95.2 फीट पंख की चौड़ाई
4. 16.11 फीट ऊंचाई
5. 7, 650 किलोग्राम वजन
6. 3736 लीटर ईंधन क्षमता
7. 1100 हॉर्स पावर एयर कूल्ड रेडियल पिस्टल इंजन
8. 370 किलोमीटर प्रतिघंटा अधिकतम गति
9. 333 किलोमीटर प्रतिघंटा सामान्य गति

इस देश के लोग हैं नौकरी से सबसे संतुष्ट

दुनिया में सबसे ज्यादा संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में नौकरी पेशा लोग अपने काम से संतुष्ट हैं। यह बात गैलप वर्ल्ड पोल द्वारा जारी एक सर्वेक्षण में सामने आई है। इस सप्ताह जारी सर्वेक्षण के नतीजों के अनुसार 128 देशों में कराए गए सर्वे में हर देश में 1,000 लोगों को शामिल किया गया जिनमें तीन देशों में सबसे ज्यादा कर्मचारी अपनी नौकरियों से संतुष्ट पाए गए। इनमें यूएई अव्वल स्थान पर है, जबकि दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः रूस और अमेरिका हैं।

क्या है

1. यूएई में सबसे कम 31 फीसदी लोग पूर्णकालिक रोजगार की तलाश में पाए गए। जबकि 58 फीसदी पूर्णकालिक रोजगार में नियोजित लोगों ने अपने काम को अच्छा बताया। इनमें से 12 फीसदी ने अपने काम को बेहतर बताया।
2. रूस में 51 फीसदी पूर्णकालिक रोजगार की तलाश में थे। 35 फीसदी के पास पूर्ण कालिक नौकरी थी और उन्होंने अपने काम को अच्छा बताया, जबकि 13 फीसदी ने बेहतर बताया।
3. अमेरिका में 56 फीसदी लोग पूर्णकालिक रोजगार की तलाश में थे और 32 फीसदी के पास पूर्ण कालिक रोजगार था जिन्होंने अपने काम को अच्छा बताया जबकि 13 फीसदी ने बेहतर बताया।

शादी की उम्र न होने पर भी लिव इन रिलेशनशिप

सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर व्यक्ति की साथी चुनने की पसंद को महत्व दिया है। कोर्ट ने कहा है कि दो वयस्क विवाह योग्य आयु न होने पर भी लिव इन रिलेशनशिप में साथ रह सकते हैं। कोर्ट ने 20 वर्ष के लड़के से शादी करने वाली 19 वर्ष की लड़की को साथ साथ रहने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने शादी को अमान्य मान कर लड़की को पिता के घर वापस भेजने का केरल हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया है।

क्या है

1. यह फैसला न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी व न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल लड़के की याचिका स्वीकार करते हुए सुनाया है। इस मामले में लड़की लड़का दोनों हिन्दू हैं।
2. कोर्ट ने कहा कि मौजूदा मामले में लड़का लड़की दोनों वयस्क हैं। लड़की 19 वर्ष की है और लड़के की आयु को लेकर विवाद है जो कि अभी 21 वर्ष का नहीं हुआ है। लड़के की जन्मतिथि 20 मई 1997 है जो कि इसी माह 30 मई को 21 वर्ष का होगा। जबकि दोनों की शादी गत वर्ष 12 अप्रैल 2017 को हुई थी।
3. सुप्रीम कोर्ट ने तथ्यों को दर्ज करते हुए फैसले में कहा है कि हिन्दू विवाह अधिनियम में विवाह के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ लड़के की आयु 21 वर्ष की न होने के आधार पर विवाह को शून्य नहीं माना जा सकता।
4. कोर्ट ने हिन्दू विवाह अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कहा कि कानून में ऐसी शादी शुरू से शून्य नहीं होती बल्कि शून्य घोषित कराई जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि वैसे वो कानून के

क्या था मामला

1. इस मामले में शादी गत वर्ष अप्रैल में हुई थी। शादी के वक्त लड़की की आयु 19 और लड़के की 20 थी। लड़की के पिता ने बेटी के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखाई।
2. बाद में मामले की सही से जांच न होने का आधार देते हुए हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट में पुलिस ने लड़का लड़की दोनों को पेश किया।
3. हाईकोर्ट ने लड़की की आयु 21 वर्ष से कम होने के कारण शादी को अमान्य घोषित कर दिया और लड़की को वापस पिता के घर भेज दिया था। जिसके खिलाफ लड़के ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।

- इस विस्तार में नहीं जाना चाहता। इसके अलावा भी देखा जाए तो दोनों वयस्क हैं। ऐसे में अगर वे शादी योग्य उम्र न होने के कारण शादी नहीं कर सकते, तो भी उन्हें बिना शादी साथ रहने का अधिकार है।
- कोर्ट ने कहा कि कानून में भी लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दी गई है। इसे घरेलू हिंसा कानून 2005 में मान्यता दी गई है।
 - कोर्ट ने हादिया मामले में दिये गये हाल के फैसले को उद्धृत करते हुए व्यक्ति की पसंद के संवैधानिक मौलिक अधिकार पर एक बार फिर मुहर लगाई है। कोर्ट ने पसंद के अधिकार से संबंधित हादिया केस के फैसले के कई पैराग्राफ इस आदेश में उद्धृत किये हैं। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में लड़की ने लड़के साथ रहने की इच्छा जताई है इसलिए हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया जाता है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में लड़की की ओर से कोई पेश नहीं हुआ था इसलिए ये लड़की की इच्छा पर निर्भर करेगा कि वो किसके साथ रहना चाहती है।

स्मार्ट सिटी पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन

सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को रफ्तार देने की दिशा में कारगर पहल शुरू कर दी है। इसके लिए पहली बार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आठ और नौ मई को होगा। इसमें सभी 99 स्मार्ट सिटी के प्रमुखों समेत स्थानीय शहरी निकाय के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। इसका उद्देश्य स्मार्ट सिटी मिशन को गति देने के लिए एक दूसरे की उपलब्धियों से सीखना है।

क्या है

- सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी करेंगे। शहरीकरण के अभियान को तेज करने के लिए 25 जून 2015 को स्मार्ट मिशन की शुरुआत की गई थी। सम्मेलन में स्मार्ट सिटी सेंटर की स्थापना, सड़कों का आधुनिक डिजाइन तैयार करने और इमारतों की छतों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाने जैसी परियोजनाओं पर विचार-विमर्श किया जाएगा।
- स्मार्ट सिटी परियोजनाओं पर अमल करने वाली कंपनियों (एसपीवी) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमुख कड़ी हैं, जो परस्पर विभिन्न शहरों के बेहतरीन कार्यों पर चर्चा करेंगे।
- अपने प्रदर्शन में पिछड़े रहे स्मार्ट शहरों को इससे सीखने को मिलेगा। यह जानकारी शहरी विकास मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी। इसमें स्मार्ट सिटी के प्रभारी अधिकारियों के साथ संबंधित राज्य व केंद्र सरकार के अधिकारी भी हिस्सा लेंगे।

जेवर एयरपोर्ट को सैद्धांतिक मंजूरी

केंद्र सरकार ने जेवर एयरपोर्ट को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रभु ने 8 मई 2018 को इसका एलान किया। जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण (येडा) के माध्यम से पिछले महीने ही नागर विमानन मंत्रालय अनुरोध भेजा था।

क्या है

- मंत्रालय की स्टियरिंग कमेटी की सिफारिश के बाद नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रभु ने इस पर मुहर लगा दी है। पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी के बाद जून में हवाई अड्डे के निर्माण के लिए ग्लोबल निविदाएं आमंत्रित किए जाने की संभावना है। अक्टूबर में हवाई अड्डे का शिलान्यास होने की संभावना है।
- स्टियरिंग कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए सुरेश प्रभु ने पुणे के पुरंदर में बनने वाले नए (ग्रीनफील्ड) एयरपोर्ट को साइट क्लियरेंस दे दी। महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी लि. (एमएडीसी) इस परियोजना का

- कार्यान्वयन करेगी। रक्षा विभाग से बात कर एमएडीसी मौजूदा एयरपोर्ट को भी सिविल उपयोग में बनाए रखने का प्रयास करेगा।
3. प्रभु ने कहा कि सरकार नभ (नेक्स्ट जनरेशन एयरपोर्ट्स फॉर भारत) निर्माण योजना के तहत हवाई अड्डों की क्षमता बढ़ाने को कृतसंकल्प है।
 4. इस योजना के तहत महत्वपूर्ण अंग हैं-उचित व समान भूमि अधिग्रहण, क्षेत्रीय विकास के लिए दीर्घकालिक मास्टर प्लान तथा सभी पक्षकारों को संतुलित आर्थिक लाभ।
 5. उन्होंने कहा कि 'उडान' स्कीम के तहत 56 नए हवाई अड्डों को जल्द से जल्द चालू कराने के अलावा यात्री सेवाओं में सुधार तथा कारगो हैंडलिंग सुविधाओं में बढ़ोतरी पर उनका विशेष जोर रहेगा।

एशिया-प्रशांत क्षेत्र में भारत चौथी सबसे बड़ी शक्ति

एशिया-प्रशांत क्षेत्र के 25 देशों में भारत कुल मिला कर चौथी सबसे प्रमुख शक्ति है। एक रपट में इसे भविष्य की विशाल शक्ति बताया गया है लेकिन रक्षा नेटवर्क और आर्थिक संबंधों के मामले में यह अभी भी पीछे है। लोवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स में एशिया - प्रशांत क्षेत्र के 25 देशों को विभिन्न पैमानों पर परखा जाता है। यह सूचकांक पश्चिम में पाकिस्तान तो उत्तर में रूस और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड तक को अपने अध्ययन में शामिल करता है।

क्या है

1. इसमें किसी देश की एक बड़ी शक्ति के रूप में रैंकिंग उसके आर्थिक संसाधनों, सैन्य क्षमता, लचीलेपन, भविष्य की प्रवृत्तियां, राजनयिक प्रभाव, आर्थिक संबंध, रक्षा नेटवर्क और सांस्कृतिक प्रभाव जैसे आठ मानकों पर परखने के बाद की जाती है।
2. ऑस्ट्रेलिया के थिंकटैंक द लोवी इंस्टीट्यूट की इस पहली सूचकांक रपट में सभी पैमानों पर मिलाकर भारत का स्थान चौथा रहा है। रपट के अनुसार, जापान और भारत दोनों बड़ी शक्तियां हैं। जापान जहां स्मार्ट शक्ति है वहीं भारत भविष्य की विशाल शक्ति है।
3. रपट में अमेरिका जहां पूर्व - प्रतिष्ठित शक्ति है, वहीं चीन एक उभरती महाशक्ति है जो तेजी से अमेरिका के बराबर पहुंच रही है। संस्थान ने कहा, "दुनिया की चार बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से तीन एशिया में है। अमेरिका प्रशांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्था है। 2025 तक दुनिया की दो तिहाई आबादी एशिया में होगी जबकि मात्र दस प्रतिशत आबादी ही पश्चिम में रह रही होगी।"
4. इस सूचकांक में भारत को आर्थिक संसाधन, सैन्य क्षमता, राजनयिक प्रभाव के मानकों पर चौथे स्थान पर जबकि लचीलेपन में पांचवे स्थान पर रखा गया है।
5. सांस्कृतिक प्रभाव और भविष्य की प्रवृत्तियों को लेकर यह तीसरे स्थान पर रहा है जबकि आर्थिक संबंध के मानक पर सातवें और रक्षा नेटवर्क के मामले में 10 वें स्थान पर रहा है।
6. इस प्रकार कुल मिलाकर भारत को इस सूचकांक पर चौथा स्थान मिला है।

दुनिया के सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री करेंगे शासन

मलेशिया के आम चुनाव के बुधवार को आए नतीजों के मुताबिक 92 वर्षीय दिग्गज नेता महातिर मोहम्मद के नेतृत्व वाले गठबंधन को जीत मिली है। वह प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही छह दशक पुराने नेशनल फ्रंट का शासन समाप्त हो गया है। महातिर के गठबंधन को 222 सदस्यीय संसद में 112 सीटों पर जीत दर्ज की है, जो सामान्य बहुमत है। जबकि सत्तारूढ़ गठबंधन 76 सीटों पर सिमट गई है। परंपरा के मुताबिक महातिर को सुल्तान मुहम्मद पंचम के

सामने शपथ लेनी है। इसके साथ ही वह दुनिया के सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री बन जाएंगे। रोचक बात यह है कि उन्हें यह मुकाम दिलाने में मलेशिया के युवाओं ने अहम भूमिका निभाई।

क्या है

1. 1981 से 2003 तक वह मलेशिया के प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी निभा चुके हैं।
2. 1976 में महातिर ने पहली बार उप प्रधानमंत्री बने और इस पद पर पांच साल तक रहे।
3. 1964 में पहली बार संसद के लिए चुने गए, इससे पहले यूएनएमओ पार्टी के सदस्य रहे।

अब हिंदी में भी होगी इंजीनियरिंग की पढ़ाई

इंजीनियरिंग की पढ़ाई अब अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी माध्यम में भी होगी। तकनीकी संस्थानों को इससे जुड़े कोर्सों को अब हिंदी माध्यम में पढ़ाने की भी स्वतंत्रता मिलेगी। सरकार ने इसे लेकर तकनीकी संस्थानों को सहूलियत दी है। साथ ही इसे प्रोत्साहित करने के लिए इंजीनियरिंग से जुड़ी किताबों को हिंदी में तैयार करने की पहल भी की है। सरकार का मानना है कि इससे छात्रों में इंजीनियरिंग को लेकर रुझान और बढ़ेगा, क्योंकि अभी भाषाई दिक्कत के चलते बड़ी संख्या में छात्र इंजीनियरिंग की पढ़ाई से कतराते हैं। एआईसीटीई से जुड़े किसी भी कोर्स को हिंदी में पढ़ाने पर अब कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई भी संस्थान हिंदी माध्यम में इसकी पढ़ाई करा सकते हैं।

क्या है

1. इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी माध्यम में कराने की यह पहल अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने की है। हाल ही में सरकार ने भी इसे मंजूरी दी है। हालांकि संस्थानों पर इसे जबरन नहीं थोपा जाएगा, बल्कि वह अपनी मर्जी से अपने संस्थान में इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी और अंग्रेजी में से किसी भी माध्यम में कराने के लिए स्वतंत्र रहेंगे।
2. एआईसीटीई का मानना है कि यह पहल काफी पहले होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी राह में सबसे बड़ी बाधा पाठ्य पुस्तकों की कमी थी। जिसे अब दूर करने की कोशिश की जा रही है।
3. इंजीनियरिंग से जुड़ी किताबों को हिंदी में तैयार करने वाले लेखकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह ने इसी कड़ी में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम से जुड़ी किताबों को तैयार करने वाले लेखकों को पुरस्कृत भी किया है।
4. माना जा रहा है कि सरकार की इस पहल से इंजीनियरिंग संस्थानों को उबारने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि मौजूदा समय में देश में इंजीनियरिंग संस्थान बड़ी संख्या में सीटों के खाली रहने से बंद हो रहे हैं।
5. गौरतलब है कि तकनीकी शिक्षा से जुड़े आईआईटी और इंजीनियरिंग कालेजों का संचालन एआईसीटीई के नियमों के तहत होता है। इन्हें अपने यहां संचालित होने वाले प्रत्येक कोर्स को एआईसीटीई से अनुमति लेनी जरूरी है।

भारतीय छात्रों का बड़ा समूह अमेरिका में काम करने में सक्षम : प्यू रिपोर्ट

शोध करने वाली संस्था प्यू ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि 2004 से 2016 के बीच अमेरिकी कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में ऑप्शनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत काम करने वाले विदेशी छात्रों में भारतीय स्नातकों की संख्या सबसे ज्यादा थी। इस समय में तकरीबन 15 लाख विदेशी छात्रों ने अमेरिका में काम किया। प्यू रिसर्च सेंटर ने सरकारी आंकड़ों के अध्ययन के बाद बताया कि इस सूची में चीनी छात्र दूसरे नंबर पर हैं। इसके बाद सूची में दक्षिण कोरियाई छात्रों ने इस अवधि में अमेरिका में काम किया है।

क्या है

1. यूएस इम्पीग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट की ओर से जारी आंकड़ों का अध्ययन करने के बाद प्यू रिसर्च सेंटर ने कहा कि ओपीटी के तहत अमेरिका में काम करने के लिए अधिकृत भारतीय छात्रों की हिस्सेदारी 4,41,400 यानी 30 फीसदी थी, जो सबसे ज्यादा है। प्यू ने यह आंकड़े फ्रीडम एंड इनफॉर्मेशन एक्ट के तहत हासिल किए हैं।
2. रिपोर्ट में कहा गया है कि 2004 से 2016 के बीच ओपीटी में हिस्सा लेने वाले तकरीबन 56 फीसदी छात्रों निजी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से स्नातक किया था। चीन के छात्र इस सूची में 21 फीसदी आंकड़ों के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि दक्षिण कोरियाई छात्रों का प्रतिशत छह फीसदी रहा।
3. प्रत्येक चार में से एक छात्र निजी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने वालों में शामिल रहा। इसमें से 38 फीसदी कॉलेज या यूनिवर्सिटी गैरलाभकारी थे, जबकि महज तीन फीसदी लाभ वाले संस्थान थे।
4. ओपीटी के तहत एनरोल तीन फीसदी से कम छात्रों ने ऐसे संस्थानों से स्नातक किया, जो कारनेगी क्लासिफिकेशन सिस्टम के तहत पंजीकृत नहीं थे। ओपीटी प्रोग्राम एफ1 वीजा प्रोग्राम के तहत अमेरिका सरकार द्वारा एक तरह का पंजीकरण सिस्टम है, जिसके तहत विदेशी छात्रों को 12 से 36 माह के लिए उनकी पढ़ाई से संबंधित क्षेत्र में नौकरी करने का मौका मिलता है।

पोखरण टेस्ट

भारत ने राजस्थान के पोखरण में 11 मई और 13 मई 1998 को पांच परमाणु परीक्षण किए। इस परीक्षण ने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। उस वक्त विदेश मंत्रालय में सेक्रेटरी (वेस्ट) थे ललित मान सिंह।

पहले के तीन परीक्षण 11 मई को 3 बजकर 45 मिनट पर किए गए। जबकि, 12 मई को बाकी दो परीक्षण हुए। यह परीक्षण विदेश सचिव के. रघुनाथ की तरफ से अपने अमेरिकी समकक्षीय को यह भरोसा देने के बावजूद किया गया कि भारत की परमाणु परीक्षण करने का ऐसा कोई इरादा नहीं है। मानसिंह ने याद करते हुए कहा- “यह परीक्षण पूरी तरह से गुप्त था। सिर्फ पांच लोग ही इस बारे में जानते थे। जाहिर तौर पर मैं या फिर विदेश सचिव उन पांचों में शामिल नहीं थे।”

क्या है

1. इस परीक्षण के बाद भारत के सामने कई मुसीबतें एक साथ आ गईं और आर्थिक, सैन्य प्रतिबंध लगाकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग कर दिया गया।
2. उस वक्त की सबसे पहली चुनौती थी अंतरराष्ट्रीय बौखलाहट को कम करना और अमेरिका के साथ विश्वास में आए अंतर को पाटना। परमाणु परीक्षण के फौरन बाद अमेरिका ने विदेश सचिव स्तर की वार्ता को सस्पेंड कर दिया। दो वर्षों के दौरान अमेरिका ने करीब 200 से ज्यादा कंपनियों को प्रतिबंधों की सूची में डाला।
3. इस लिस्ट में सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ एटोमिक एनर्जी (डीएई), डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (डीआरडीओ) और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की कंपनियों का नाम ही शामिल नहीं था बल्कि कई उन प्राइवेट फर्म को भी इस सूची में डाला गया जो उनके साथ पहले से काम कर रहे थे।
4. उस समय तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री स्ट्रोब टेलबोट और भारतीय विदेश मंत्री जसवंत सिंह की बीच लंबी चर्चा हुई। उन्होंने सात देश, 10 शहर और 14 राउंड की वार्ता की।
5. अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए भारत एक न्यूक्लियर हब बन गया। पाकिस्तान भी उसकी बराबरी करना चाहता था। जिसके बाद अमेरिका को इस बात का डर सता रहा था कि दक्षिण एशिया परमाणु शक्ति का अखाड़ा बन जाएगा। इस मामले में टेलबोट और जसवंत सिंह के बीच हुई बातचीत काफी मददगार बनी।

ब्रिटेन में अमीरों की सूची में हिंदुजा बंधु

भारत में जन्मे हिंदुजा बंधु ब्रिटेन के अमीरों की सालाना सूची में दूसरे स्थान पर आ गए हैं। रसायन क्षेत्र के उद्यमी जिम रैटक्लिफ ने उन्हें दूसरे स्थान पर पछाड़ दिया है। संडे टाइम्स की अमीरों की सूची के अनुसार, लंदन स्थित श्रीचंद और गोपीचंद हिंदुजा 20.64 अरब पाउंड की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर है। 21.05 अरब पाउंड के साथ रैटक्लिफ पहले स्थान पर हैं। ब्रिटेन के एक हजार अमीरों की 2018 की सूची में 47 भारतीय मूल के अमीर शामिल हैं।

क्या है

1. यह सूची तैयार करने वाले रॉबर्ट वॉट्स ने कहा कि ब्रिटेन बदल रहा है। वे दिन अब गए जब पुराना धन और कुछ गिने चुने उद्योगों का ही संडे टाइम्स की अमीरों की सूची में दबदबा था। अब इस सूची में विरासत में धन पाने वालों के बजाय खुद बने उद्यमियों का दबदबा है।
2. रॉबर्ट ने कहा कि अब अमीरों की सूची में चॉकलेट का कारोबार करने वाले, सुशी, पेट फूड और अंडों का कारोबार करने वाले शामिल हो रहे हैं।
3. सूची में वे सामान्य पृष्ठभूमि वाले लोग आ रहे हैं, जिन्होंने स्कूली दिनों में संघर्ष किया और काफी समय से कारोबार की शुरुआत की।
4. सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाले रैटक्लिफ ने रसायन कंपनी आईनियोस की शुरुआत की। वर्ष 2017 की सूची में वह 18वें स्थान पर थे। पिछले साल के दौरान उन्होंने 15.3 अरब पाउंड जोड़े और वह पहले स्थान पर पहुंच गए हैं।

रोहतगी की लोकपाल चयन समिति में नियुक्ति

केन्द्र ने 15 मई 2018 को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि पूर्व अटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी की लोकपाल चयन समिति में विधिवेत्ता के रूप में नियुक्ति की गई है। यह पद सितंबर, 2014 में वरिष्ठ अधिवक्ता पी. पी. राव के निधन की वजह से रिक्त था। जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ को अटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल ने सूचित किया कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 11 मई को चयन समिति की बैठक में प्रमुख विधिवेत्ता के रूप में रोहतगी को नियुक्त करने का फैसला किया गया। चयन समिति में प्रधानमंत्री, प्रधान न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता और एक प्रमुख विधिवेत्ता शामिल हैं।

क्या है

1. केन्द्र में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद 2014 में मुकुल रोहतगी को अटर्नी जनरल नियुक्त किया गया था। उन्होंने जून, 2017 में इस पद से इस्तीफा दे दिया था। लोकपाल चयन समिति में विधिवेत्ता का पद 11 सितंबर, 2017 को वरिष्ठ अधिवक्ता पी. पी. राव का निधन होने के बाद से रिक्त था।
2. बेंच ने अटर्नी जनरल की दलील सुनने के बाद इस मामले की सुनवाई 2 जुलाई के लिए स्थगित कर दी। बेंच गैर सरकारी संगठन कामन कॉज की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल 27 अप्रैल के फैसले के बावजूद लोकपाल की नियुक्ति नहीं किए जाने का मुद्दा उठाया गया है।
3. लोकपाल की तत्काल नियुक्ति के लिए इस संगठन और कुछ अन्य की याचिका पर ही शीर्ष अदालत ने अपना फैसला सुनाया था।
4. केन्द्र ने 17 अप्रैल को शीर्ष अदालत से कहा था कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में समिति की हाल में हुई बैठक में लोकपाल का चुनाव करने वाली समिति में प्रमुख विधिवेत्ता को शामिल करने के लिए एक नाम की सिफारिश की गई है, जिसकी स्वीकृति का इंतजार है।

5. इस पर शीर्ष अदालत ने कहा था कि चूंकि इस दिशा में कदम उठाए गए हैं, इसलिए इस समय कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि लोकसभा में विपक्ष के नेता सहित प्रस्तावित संशोधन संसद से पारित होने तक लोकपाल कानून लागू किए जाने को लटकाए रखना न्यायोचित नहीं है।

शशांक मनोहर दूसरी बार चुने गए आईसीसी के चेयरमैन

शशांक मनोहर मंगलवार को निर्विरोध दूसरी बार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के अध्यक्ष चुने गए। आईसीसी द्वारा जारी किए गए बयान के मुताबिक, शशांक इस पद के लिए इकलौते दावेदार थे। शशांक पहली बार 2016 में इस पद पर बैठे थे। उन्होंने कहा, एक बार फिर आईसीसी का चेयरमैन बनना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं इसके लिए आईसीसी के निदेशक का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने लगातार मेरा समर्थन किया।

क्या है

1. उन्होंने कहा, पिछले दो साल में हमने कई बड़े कदम उठाए हैं। मैं जब 2016 में इस पद पर बैठा था तब जो वादे किए उनका पूरा किया है।
2. भारत के रहने वाले शशांक ने कहा, अगले दो साल में हम अपने सदस्यों के साथ मिलकर वैश्विक स्तर पर खेल को आगे ले जाने के लिए काम करेंगे।
3. खेल अच्छी स्थिति में, लेकिन हम इसकी देखभाल करने वाले हैं। हमें लगातार मेहनत करनी होगी।

प्रख्यात भौतिकशास्त्री का निधन

भारतीय अमेरिकी भौतिकशास्त्री ई. सी. जॉर्ज सुदर्शन का 13 मई 2018 को निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार बृहस्पतिवार को टेक्सास के आस्टिन में किया जाएगा। पारिवारिक सूत्रों और करीबी मित्रों के मुताबिक 86 वर्षीय सुदर्शन का सामान्य कारणों से निधन हो गया। उनके परिवार में पत्नी भामती सुदर्शन और दो बच्चे हैं।

क्या है

1. सुदर्शन ने टेक्सास विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के तौर पर 40 वर्ष से भी अधिक समय तक काम किया था।
2. प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार के लिए नौ बार उनके नाम की सिफारिश की गयी थी लेकिन उन्हें यह पुरस्कार नहीं मिला था।